कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला

कांग्रेसनीत यूपीए पर पुती कोयले की कालिख.......... 6

लेख

'कोलगेट' पर प्रधानमंत्री का लचर बचाव
–**लालकृष्ण आडवाणी**.......... 11

कोयला ब्लॉक आवंटनों की संदिग्ध वकालत
–**अरुण जेटली**.......... 14

संसद में भाजपा गतिरोध पर आलोचक कांग्रेस का रिकार्ड देखें
– **यशवंत सिन्हा**.......... 16

सरकार कार्रवाई न करे तो संसद में चर्चा का क्या लाभ !
– **निर्मला सीतारमन**.......... 18

यूपीए सरकार जानती ही नहीं कि कोई संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है!
–**अम्बा चरण वशिष्ठ**.......... 20

पं दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर विशेष

एकात्ममानव दर्शन के मंत्रद्रष्टा
–**डॉ. शिव शक्ति बक्सी**.......... 23

पुस्तक समीक्षा

राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि
–**विकाश आनंद**.......... 25

अन्य

भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का मणिपुर प्रवास.......... 8
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ.......... 9
आन्ध्र प्रदेश भाजपा का तेलंगाना पर धरना.......... 10
भाजयुमो का कोयला ब्लॉक आवंटन घाटाले के विरोध में प्रदर्शन.......... 13
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न.......... 19

ऐतिहासिक चित्र

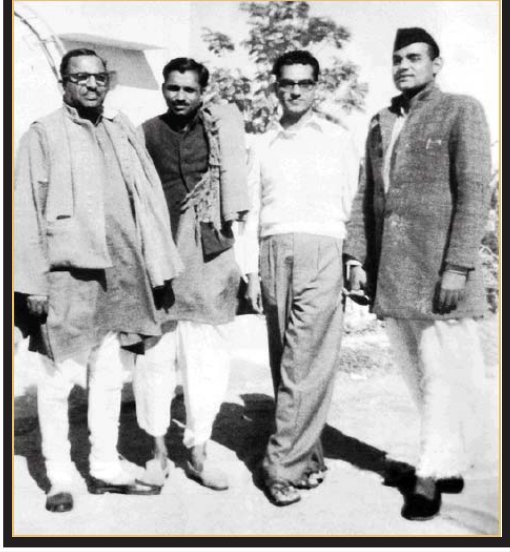

भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री पं दीनदयाल उपाध्याय, के साथ- श्री केदारनाथ साहनी (एकदम बाएं), श्री के.आर. मलकानी (बाएं से तीसरे) व श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

राष्ट्रीय कौन ?

भारत में राष्ट्रीय कौन है, कौन देशी है और कौन विदेशी, यह प्रश्न प्राय: अनेक बार उठ खड़ा होता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी सियार और सिंह के बच्चों की यह रोचक कथा सुनाते थे।

एक बार एक सियार का बच्चा जंगल में घूमते समय अपनी माँ से बिछुड़ गया। शाम हुई तो भूख और डर के मारे वह रोने लगा। उसी समय वहाँ से एक शेरनी जा रही थी। रोते बच्चे को देख वह उसे अपनी गुफा में ले आयी। उसे दूध पिलाया और अपने बच्चों के साथ-साथ उसका लालन-पालन भी करने लगी। धीरे-धीरे वह सियार का बच्चा शेर के बच्चों से घुलमिल गया। वह भी उनके साथ दिन भर जंगल में घूमता, खेलता और रात में शेरनी का दूध पीकर सो जाता। वह सियार का बच्चा शेर के बच्चों से आयु में बड़ा था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें एक हाथी दिखायी दिया। शेर के बच्चे बहुत खुश हुए। वे बोले आज बहुत दिनों बाद मोटा-ताजा शिकार मिला है, आओ इसे मार डालें।

यह देखकर सियार का बच्चा बोला - अरे, क्या करते हो? देखते नहीं, यह हमसे शरीर में कितना बड़ा और बलवान है। यदि हमने इस पर हमला किया, तो यह हमें ही मार डालेगा। शेर के बच्चे नहीं माने, वे हाथी पर हमला करने की तैयारी करने लगे। यह देखकर सियार का बच्चा दौड़ता हुआ घर आया। उसने शेरनी को कहा - माँ, देखो मेरे छोटे भाई मेरी बात नहीं मानते। वे अपने से बहुत बड़े हाथी से लड़ रहे हैं। वह उन्हें मार डालेगा।

शेरनी ने हँसकर कहा - यह ठीक है कि तुम मेरा दूध पीकर बड़े हुए हो, पर तुम हो तो सियार ही। तुम्हारे वंश में कोई हाथी से नहीं लड़ता, पर हमारे यहाँ तो यह सामान्य सी बात है। इसलिए अच्छा यही है कि अब तुम अपने घर चले जाओ। ऐसा न हो कि मेरे बच्चे हाथी को मारने के बाद तुम पर ही हमला न बोल दें।

इस कथा का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर हमारे देश में रहने लगे, तो केवल इतने मात्र से ही वह भारत का राष्ट्रीय नहीं हो जाता। राष्ट्रीयता तो एक परम्परा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले संस्कारों से दृढ़ होती है।

-'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

व्यंग्य चित्र

सभी सुधी पाठकों को कमल संदेश परिवार की ओर से 'गणेश चतुर्थी' की हार्दिक शुभकामनाएं!

इनका कहना है...

''कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर संसद का गतिरोध दूर करने के लिए राजग ने प्रस्ताव दिया है कि सभी आवंटन रद्द कर दिए जाएं और उस प्रक्रिया की जांच की जाए, जिसके तहत चयन समिति ने इन आवंटनों का फैसला दिया।''

- **लालकृष्ण आडवाणी,** अध्यक्ष, भाजपा संसदीय दल

''कोयला ब्लॉक आवंटन में हुई अनियमितताओं के खिलाफ जारी लड़ाई में पूरा विपक्ष एकजुट है। संसद सत्र का अवसान हुआ है, विपक्ष ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। भाजपा इस मसले को लेकर जनता के बीच जाएगी।''

- **सुषमा स्वराज,** नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

''कोयला आवंटन में हुए घोटाले पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी का हवाला दिया है। अदालत में आरोपी को चुप रहने का अधिकार है लेकिन एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता।''

- **अरुण जेटली,** नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा

प्रधानमंत्री ने कुर्सी तो बचा ली लेकिन साख नहीं

dkग्रेसनीत यूपीए यह समझ रही होगी कि विपक्ष की मांग को हमने ठुकरा दिया। डॉ. मनमोहन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस यह कहकर इतरा सकती है परन्तु ठप्प संसद ने भारत के एक-एक नागरिक तक यह बात तो पहुंचा दी कि कोयला आवंटन में हुए करोड़ों के घोटाले में पूरी की पूरी कांग्रेस काली हो चुकी है। संसद में बहस से जितना असर नहीं होता उससे ज्यादा यूपीए सरकार पर कहर ढाया है ठप्प संसद ने। संसद का न चलना, बहस का न होना, इस्तीफा नहीं देना, इससे कांग्रेस कुर्सी तो बचा ले गई है लेकिन देश की जनता में यह बात साफ तौर पर चली गई कि पूरी की पूरी कांग्रेस अब देश के लिए नहीं पर कुर्सी के लिए है।

आखिर भाजपा गलत क्या कह रही थी। यही तो कह रही थी कि अगर 2जी स्पेक्ट्रम में मंत्री रहते ए. राजा के इस्तीफा देना पड़ा तो यदि कोयले की दलाली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं? जनतंत्र की चिंता यदि कांग्रेस को होती तो न प्रधानमंत्री विदेश जाते और न सोनिया गांधी। इन्होंने चलते सदन में भी अपनी चिंता की, देश की नहीं।

भाजपा सहित सभी विपक्षी दलों को अब संसद को चहारदीवारी से बाहर उन सड़कों पर आना होगा जिनके किनारे जनतंत्र की रक्षा करने वाली जनता जर्नादन रहती है। भारत में सड़कों पर आंदोलन से ही लोग संसद में जाते हैं। कांग्रेसी माने या न माने देश 16वीं लोकसभा का गठन चाहता है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल। सारा देश उद्वेलित है। घोटालों के घुटन से घुट रही संसद की चीत्कार यदि भारत नहीं सुनेगा तो आने वाले दिनों में हम भारत माता को मजबूती प्रदान नहीं कर पायेंगे और 21वीं सदी में जहां भारत को पहुंचाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचा पायेंगे।

संसद के सेन्ट्रल हॉल में दबी जबां से यह बात तो आने लगी कि कांग्रेस न देश का भविष्य है और न ही कांग्रेस का कोई भविष्य है। ये बातें वे कह रहे थे जो कांग्रेस के नेता और सांसद हैं। हताशा एवं निराशा के गर्त में डूबी कांग्रेस ने विश्व के बाजार में भारत की साख पर बट्टा लगाया है। साख के जिस सेंसेक्स को अटलजी ने अपने कार्यकाल में जितनी ऊंचाई दी, यूपीए के आठ वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस एवं डॉ. मनमोहन सिंह ने उसे उतना ही नीचे गिरा दिया है। अटल जी के जमाने में पोखरण विस्फोट के दौरान पांच महाशक्तियां कहलाने वाले राष्ट्रों ने यह एलान कर दिया था कि अब भारत को कोई मदद नहीं करेंगे, वहीं विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने अटल जी से कहा था कि इन महाशक्तिशाली राष्ट्रों में हम भारतीय रहते हैं, अटलजी चिंता न करें अभी तो हजारों करोड़ भेज रहे हैं, और भेजेंगे पर इन महाशक्तियों के आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं वे दिन थे और अब ये दिन हैं! कैसे थे वे दिन, अब कैसे हैं ये दिन?

गलत हाथों में पतवार होती है तो नाव को डूबने से कौन बचाएगा। सन् 2004 ने देश में जानबूझकर भले ही अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए को पराजित करने की भूल की हो पर सच तो यही है कि जनता जर्नादन के कारण ही खंडित जनादेश मिला और देश की लोकतंत्र की पतवार उनके हाथों में चली गई जिन हाथों से देश का चेहरा झुलसता चला आ रहा था। तनिक सा विचार करें- अगर यह वाकया न हुआ होता तो भारत आज कहां होता। कांग्रेस एक साजिश है, षड्यंत्र हैं, गिरोह है, कार्पोरेट सेक्टर की तरह चलने वाली कम्पनी है। अब न यह कोई दल है न इनके पास कोई नेता है। यह तो आजादी वाली कांग्रेस की पुण्याई पर राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। देश संवरे और संभले, यह चिंता सिर्फ भाजपा की नहीं संपूर्ण भारत की है। अत: अब विपक्षी संसद सदस्यों को सड़क पर आना ही होगा और सड़क के संघर्षों से एक सुव्यवस्थित प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी लोकसभा का गठन कर जनता की आशाओं पर खरा उतरना होगा। ■

कांग्रेसनीत यूपीए पर पुती कोयले की कालिख

संजीव कुमार सिन्हा

n रद्रष्टा महात्मा गांधी ने सही सुझाव दिया था, ''देश की आजादी के बाद कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए।'' यदि उनकी बात मान ली गयी होती तो आज देश को यह दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। वैसे तो आजादी के बाद से ही कांग्रेस शासन में घोटालों का दौर शुरू हो गया था लेकिन वर्तमान कांग्रेसनीत यूपीए शासन में गत आठ सालों से एक के बाद एक महाघोटाले हो रहे हैं और हर घोटाला पिछले घोटाले से बड़ा साबित हो रहा है। संसद में लगातार कोई न कोई घोटाला उजागर हो रहा है। वास्तव में, यूपीए सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई है। इसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। हाल ही में यूपीए के मंत्रियों और सांसदों ने देश को लाखों-करोड़ों रुपये का चपत लगाते हुए कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला को अंजाम दिया। इस घोटाले में कांग्रेसी सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक के दामन दागदार हो गए। प्रधानमंत्री की कथित 'ईमानदारी' छवि पर बट्टा लगा और यह साबित हो गया कि उनके ही हस्ताक्षर से सभी कोयला खदानें बांटी गईं। सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। पूरी कांग्रेस पर कोयले की कालिख पुत गई।

गत 17 अगस्त को संसद में कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को कौड़ियों के भाव कोयला खानों का आवंटन कर दिया। ब्लॉकों की प्रतिस्पर्धी तरीके से नीलामी न कराने की वजह से प्राइवेट कंपनियों को 1 लाख 85 हजार 591 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ और सरकार को इतने का ही नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, मनमानीपूर्ण आवंटन के बजाय इन खदानों की नीलामी की गई होती तो सरकारी खजाने में करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये का ज्यादा राजस्व आता। कैग ने कहा कि उसने यह अनुमान कोल इंडिया की वर्ष 2010-11 के दौरान

साभार : रा. पत्रिका

कोयला उत्पादन की औसत लागत और खुली खदान से कोयला बिक्री के औसत मूल्य के आधार पर लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'यदि कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां मंगाने के कई साल पहले लिए गए फैसले पर अमल कर लिया जाता तो कंपनियों को होने वाले इस अनुमानित वित्तीय लाभ का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में पहुंच सकता था।'

एक जिम्मेदार विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए घोटाले को लेकर सड़क से संसद तक आंदोलन छेड़ दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कोयला मंत्री रहते हुए यह घोटाला हुआ, इसलिए भाजपा ने सीधे उनसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा ने इस घोटाले के खिलाफ पार्टी के प्रमुख नेताओं के संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए। रैलियां निकालीं। हस्ताक्षर अभियान चलाया। धरना दिए। प्रदर्शन किए। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे और कांग्रेस नेता निर्लज्जता के साथ प्रधानमंत्री का बचाव करते रहे। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने तो कपिल सिब्बल द्वारा 2जी घोटाले में 'कोई घाटा नहीं होने' के सिद्धांत की तरह यहां तक कह दिया कि खदानों से अब तक कोयला निकाला ही नहीं गया।

याद रहे कि 2जी घोटाला के समय भी यूपीए ने इसी तरह का जिद्दी रवैय्या अपनाया। अंततः भाजपा ने संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पर जबर्दस्त दबाव बनाया तब जाकर तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री ए.राजा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह भाजपा ने तय किया कि संसद के वर्तमान मानसून सत्र की कार्यवाही तभी चलेगी जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे।

हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री सहित अनेक सांसद कोयला आवंटन घोटाला में बेनकाब हो रहे हैं। इस घोटाले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय के हाथ भी काले हो गए। सहाय ने पांच फरवरी दो हजार आठ को एक इस्पात कंपनी को कोयला खदान आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने एसकेएस इस्पात नाम की कंपनी

को खदान आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उस वक्त सुबोध कांत सहाय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हुआ करते थे। अगले ही दिन छह फरवरी दो हजार आठ को पीएमओ ने कोयला सचिव को चिट्ठी लिखकर इस कंपनी को खदान आवंटन के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा था।

इसी तरह महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा केंद्र राजेंद्र दर्डा का नाम कोयला आवंटन घोटाले में सामने आया। उनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दायर की है। उनके सांसद भाई भी एफआईआर में नामजद हैं। वे कोयला कारोबारी मनोज जायसवाल के साथी हैं।

कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को नियमों को ताक पर रखकर एक कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रेमचंद गुप्ता पर भी कोयले की कालिख लगी। उनके बेटे की नई कंपनी को महज एक महीने के भीतर कोयले की खदान मिली। गुप्ता जब कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टिर थे तब उनके बेटे ने ब्लॉक के लिए आवेदन किया, गुप्ता के कार्यकाल खत्म होने के एक महीने बाद उनके बेटे को खदान मिल गई।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच 27 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद लोकसभा और फिर राज्य सभा में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बयान देने के ठीक बाद संसद भवन के बाहर मीडिया में भी बयान दिया। प्रधानमंत्री ने उनकी 'खामोशी' पर तंज कसे जाने पर शायराना अंदाज में जवाब देते हुए शे'र पढ़ा, 'हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।'

प्रधानमंत्री के इस शे'र का जवाब देते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा, 'जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरु होने का खतरा रहता है तो आदमी चुप रहता है।' उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन का मुनाफा कांग्रेस के खाते में गया और इसके लिये उन्हें 'मोटामाल' अलग से मिला था। यदि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो यूपीए सरकार के साथ-साथ कांग्रेस भी कठघरे में होगी।

संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज से बात की। श्रीमती गांधी से बातचीत में श्रीमती स्वराज ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में जिन कोयला खंडों पर सवाल उठाया गया है उनके आवंटन को रद्द किया जाए और इस मामले की स्वतंत्र जांच हो।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा डॉ. मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग पर अडिग है। संसद में गतिरोध समाप्त करने का एकमात्र रास्ता यही है कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार हुए 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लें।

भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2जी घोटाले में तो वह अपने गठबंधन सहयोगी के मंत्रियों का इस्तीफा ले लेती है, जबकि वह अपने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को बचाती है।

मीडिया में राजग दलों में कथित मतभेद को उछाला गया और कहा गया कि इस मामले में गठबंधन एकजुट नहीं है। गठबंधन के संयोजक श्री शरद यादव ने स्पष्ट शब्दों में यह कहकर कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे, कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने और उनकी नीलामी करने की मांगों पर राजग एकजुट है, विरोधियों को चुप करा दिया।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राजग ने 8 सितम्बर को संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के इस्तीफे, कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और अपने विरोध को सड़कों पर ले जाने की घोषणा भी की। दोनों सदनों के भाजपा, जदयू, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के सांसदों ने कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राजग के सांसदों ने तख्तियां भी लहरायीं, जिन पर लिखा था: कोलगेट मुद्दे पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिये, अब संसद से सड़कों तक। राजग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, राजग के संयोजक एवं जदयू अध्यक्ष श्री शरद यादव, शिरोमणि अकाली दल की श्रीमती हरसिमरत कौर और शिवसेना के श्री अनंत गीते ने प्रदर्शन की अगुवाई की।

प्रदर्शन के बाद श्री लालकृष्ण आडवाणी ने संवाददाताओं से कहा कि आज सत्र का अंतिम दिन है और इसलिये राजग सांसदों ने यहां इकट्ठा होने और यह घोषणा करने का फैसला किया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिये हमारा प्रदर्शन संसद से सड़कों तक पहुंचेगा।■

भाजपा पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है : नितिन गडकरी

मणिपुर, समूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यह संदेश देने आया हूं कि पार्टी पूरी तरह से पूर्वोत्तर के अपने उन भाई बंधुओं के साथ है जो देश के कुछ भागों में कठिनाइयों का सामना कर रही है। मैं यहां घोषणा करता हूं कि भाजपा का सद्भावना मिशन अगले चार-पांच दिन में पूर्वोत्तर का दौरा करेगा और दोबारा आश्वासन देना चाहता हूं कि जो लोग आ गए हैं वह फिर से अन्य भागों में अपनी पढ़ाई और काम करने के लिए लौटेंगे।

मैं यहां एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों की जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए देशव्यापी अभियान चलाया है। इन लोगों को कुछ इलाकों में उनके खिलाफ हमलों जैसी अफवाहों के फैलने से चोट पहुंची और इन लोगों ने पिछले सप्ताह घर भागने की कोशिश की।

भाजपा शासित राज्य सरकारों और पार्टी की इकाइयों से प्रत्येक राज्य में सभी स्तरों पर अपने अपने तंत्र को मजबूत करने को कहा गया है ताकि शांति और सौहार्द कायम रखा जा सके और प्रभावकारी व्यवस्था द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों और युवकों की भावनाओं को शांत किया जा सके।

हमारे मुख्यमंत्री खुद विश्वास बहाली के सभी उपायों का निरीक्षण कर रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बार-बार अपील जारी कर इन लोगों से अपने काम पर लौटने को कहा है।

पार्टी ने महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों, खासतौर से बेंगलौर, हैदराबाद और पुणे में हैल्प डेस्क स्थापित किये हैं और सहायता के लिए हेल्पलाइनें स्थापित की हैं।

हाल ही में, दिल्ली में, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें हमने फैसला किया कि हमारे राज्यों में पूर्वोत्तर के भाई बंधुओं की सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मैं भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी की राज्य इकाइयों से लगातार संपर्क में हूं और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं कि पूर्वोत्तर के लोगों को समझाएं कि देश के किसी भी भाग में उनके लिए कोई खतरा नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे पूर्वोत्तर के लोगों को संरक्षण और सहायता प्रदान करें।

मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि भाजपा पूर्वोत्तर राज्यों के सभी नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि वे बिना किसी डर के देश के किसी भी भाग में यात्रा कर सकें और कहीं भी रह सकें।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा इम्फाल (मणिपुर) में 24 अगस्त, 2012 को जारी प्रेस वक्तव्य

भाजपा शासित कर्नाटक में, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और बिना किसी भेदभाव के शांति से वहां रह सकते हैं और आईटी और उद्योग के अन्य क्षेत्रों में विकास का लाभ उठा सकते हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री जगदीश शेट्टर ने मुझे आश्वासन दिया है कि बेंगलौर या राज्य के किसी अन्य शहर में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है और जिन लोगों ने पुलिस संरक्षण मांगा है उन्हें दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग जाना चाहते थे उन्हें सीधे तौर पर किसी तरह के खतरे या हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के छात्र एसोसिशन को आश्वासन दिया है, ''कर्नाटक उन सभी लोगों का है जो वहां रहते हैं। कर्नाटक असम से ज्यादा सुरक्षित है। किसी को भी दहशत नहीं होनी चाहिए या अफवाहें फैलाने वालों के दबाव में नहीं आना चाहिए।''

उन्होंने एसोसिएशन से वादा किया है कि वे उन सभी मामलों की खुद जांच करेंगे जिनमें कथित उत्पीड़न की बात कही गई है।

कर्नाटक में पुलिस से कहा गया है

कि वह अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वय कायम कर रही है।

असम हिंसा भारतीयों और विदेशियों के बीच है। असम में हिंसा की शर्मनाक घटनाएं जिनकी शुरुआत कोकराझार, चिरांग और धूबरी जिलों से हुई और बाद में राज्य के अन्य भागों में भी फैल गई वह मुख्यत: भारतीयों और विदेशियों के बीच संघर्ष था। सबसे निंदनीय इन संघर्षों में अब तक करीब 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 5 लाख लोग बेघर हुए हैं। ये संघर्ष कांग्रेस पार्टी की असम में वोट बैंक की राजनीति का नतीजा हैं। जब तक कांग्रेस असम में वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने से नहीं बचेगी, राज्य और क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी।

भाजपा सीमा पार से घुसपैठ का हमेशा से विरोध करती रही है। हम सभी घुसपैठियों को वापस भेजने और सीमा को सील करने के पक्ष में हैं ताकि भविष्य में घुसपैठ को रोका जा सके। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति बड़े पैमाने पर बंगलादेशियों की घुसपैठ के लिए जिम्मेदार है और इसके परिणामस्वरुप पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारतीय नागरिक विस्थापित हो गए हैं। लोग इस सच्चाई से अवगत हैं कि कांग्रेस ने ही आईएमडीटी अधिनियम लागू किया और घुसपैठियों को संरक्षण दिया और उसी पार्टी ने बाद में आईएमडीटी अधिनियम को अमान्य घोषित कर उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की। यह तय है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। ■

केन्द्र सरकार की जनविरोधी, व्यापारविरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के व्यापारियों ने कमर कसी

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व्यापार प्रकोष्ठ के तत्वाधान में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल धरना तथा प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के 26 प्रदेशों के हजारों व्यापारियों ने भाग लिया। इन सभी ने केन्द्र सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों की घोर भर्त्सना करते हुए पांच सूत्री मांगें उठाईं और उनके पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में अपना आंदोलन तेज करने का संकल्प किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी एवं श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी, मुरलीधर राव, श्याम जाजू, महेन्द्र पांडे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विजेन्द्र गुप्ता, जुवेल उरांव आदि ने भी श्रोताओं को सम्बोधित किया। इन सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों की तकलीफों को भाजपा संसद में उठाएगी और सरकार के हाथों राष्ट्र के व्यापार को नष्ट नहीं होने देगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री श्याम बिहारी मिश्र एवं मंच संचालन राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री घनश्याम दास अग्रवाल ने किया।

वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि व्यापारी देश की वितरण व्यवस्था की रीढ़ है। यह वर्ग भारतीय ढांचे में छोटी बड़ी दुकानों, खोखा, ठेले, पटरी के माध्यम से गांवों, कस्बों व शहरों में आम जरूरत की वस्तुएं आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। यह वर्ग कड़ी प्रतिस्पर्धा व 12 से 14 घंटे मेहनत के बाद अपनी आजीविका चलाता है। कृषि क्षेत्र के बाद भारत में दूसरा बड़ा क्षेत्र व्यापार का है, जिस पर देश की लगभग 30 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। देश के कुल राजस्व का 70 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यापारी वर्ग एकत्र करके सरकारों को जमा कराता है। इसके अलावा देश में 72 प्रतिशत रोजगार यही वर्ग उपलब्ध कराता है। आपदा-विपदा के समय में भी लोग इसी वर्ग से मदद की अपेक्षा करते हैं। इसके बावजूद भी यह समाज आज कई प्रकार की जटिलताओं से एवं केन्द्र सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों के कारण अधिकारियों के शोषण से तथा असंवैधानिक वसूली आदि से पीड़ित है और समस्याओं से लगातार जूझ रहा है।■

'केन्द्र में आते ही करेंगे तेलंगाना राज्य की घोषणा'

तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर भाजपा, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर 3, 4 एवं 5 सितम्बर को तीन दिवसीय धरना पर बैठे। 3 सितम्बर को धरना का उद्घाटन करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब कोई ताकत तेलंगाना राज्य गठन को रोक नहीं सकती। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि राजग केंद्र में सत्ता में आता है तो छह महीने के अंदर तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कोई भी वादा यूं ही नहीं करती। हम जो कहते हैं उसे पूरा करके दम लेते हैं।

दूसरे दिन 4 सितम्बर को राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार पर अनिर्णय की स्थिति में रहने का आरोप लगाते हुए वादा किया कि अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में आई तो तेलंगाना राज्य के गठन को प्रथम प्राथमिकता देगी। इस मुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के निवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने उस पर आंसूगैस के गोले दागे। श्री जेटली ने पृथक राज्य के इस मुद्दे पर संप्रग सरकार की अनिर्णय की स्थिति के लिए उसपर नीतिगत पंगुता और निर्णय लेने का अपना काम पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई वाली समिति को सौंपने का आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कांग्रेस पर तेलंगाना के लोगों के साथ लगातार धोखा करने का आरोप लगाया। वे संसद मार्ग थाने के बाहर अपने सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पार्टी नेता प्रकाश जावडेकर की अगुवाई में आगे बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तब उन्होंने बैरीकेड तोड़ने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने यूपीए सरकार की अलग तेलंगाना राज्य के गठन में कोई दिलचस्पी नहीं होने का दावा करते हुए वादा किया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो तीन महीने के भीतर अलग राज्य का गठन करेगी। श्रीमती स्वराज ने कहा कि यूपीए सरकार ने दो साल पहले देर रात अलग तेलंगाना राज्य का गठन किए जाने की घोषणा की थी लेकिन वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि यदि इस सरकार को उखाड़ फेंका गया तो तेलंगाना का गठन किया जाएगा।

धरना के तीसरे और अंतिम दिन 5 सितम्बर को कार्यकर्ताओं को संबाधित करते हुए भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ होते ही तेलंगाना अलग राज्य की घोषणा की जाएगी। श्री आडवाणी ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उत्तरांचल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। उस समय कुछ सहयोगी दलों के विरोध के कारण तेलंगाना राज्य का मामला अधर में लटक गया था किंतु अब सबसे पहले इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री आडवाणी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। तेलंगाना के गठन के बारे में पधानमंत्री एवं संप्रग सुपीमो श्रीमती सोनिया गांधी ने भी आश्वासन दिया था किंतु बाद में दोनों अपने वायदे से मुकर गए जिससे तेलंगाना की जनता में भारी आक्रोश है। तेलंगाना राज्य हर कीमत पर बनकर रहेगा। आंध्र पदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर घोषणा की कि भाजपा अपना आंदोलन और तेज करेगी।

‘कोलगेट’ पर प्रधानमंत्री का लचर बचाव

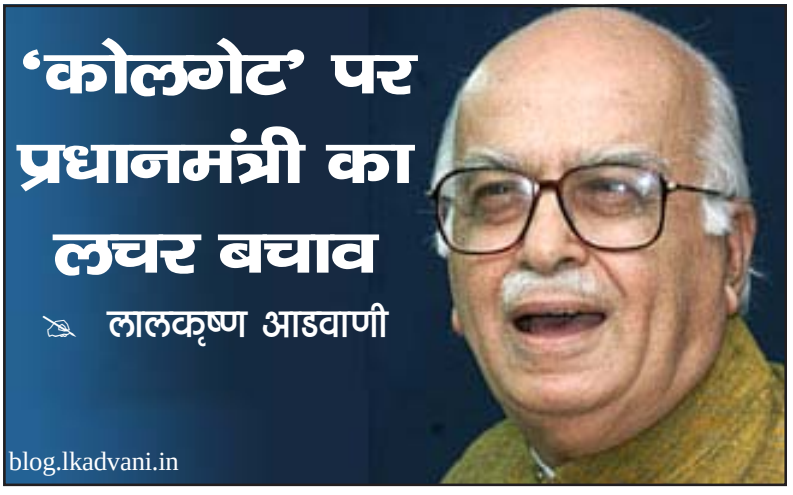

लालकृष्ण आडवाणी

blog.lkadvani.in

कोयला आवंटन को लेकर संसद में गतिरोध एक सप्ताह से ज्यादा समय से बना हुआ है। एनडीए ने इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव दिया है कि इन सभी आवंटनों को रद्द कर दिया जाए और इन्हें आवंटित करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराई जाए। सरकार इस पर अभी तैयार नहीं है।

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह लोकसभा में आए और आजकल ‘कोलगेट’ (वाटरगेट के बाद से) के नाम से पहचाने जाने वाले स्कैण्डल पर एक लम्बा वक्तव्य पटल पर रखा। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने अपुष्ट स्पष्टीकरण में संघवाद, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ही भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता ठहराया है और जिसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती, पर आरोप मढ़ा है।

कुछ भाजपा मुख्यमंत्रियों की कथित तौर पर प्रकट की गई आपत्तियों, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के डॉ. रमन सिंह को बार-बार उद्धृत किया गया कि मानों इन्हीं के चलते प्रतिस्पर्धा बोली सम्बन्धी विधि मंत्रालय का निर्णय रद्द किया गया हो।

प्रधानमंत्री के वक्तव्य में इन्हीं दोनों संदर्भों-संघवाद, और मुख्यमंत्रियों-ने मुझे आपातकाल की अवधि और इन साम्यों की तुलना हेतु स्मरण करा दिया।

रायपुर से प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में 2 मई, 2005 को डॉ. रमन सिंह द्वारा तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव को लिखे गए पत्र को ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया है, जिसमें डॉ. रमन सिंह लिखते हैं:

“यदि केन्द्र सरकार अंततः कैप्टिव माइनिंग हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए बोली का रास्ता अपनाने का निर्णय लेती है, तो ऐसे कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पाद का एक हिस्सा सरकार को जाएगा। सम्बन्धित क्षेत्रों में स्थित इन खनिजों के स्वामित्व वाले राज्यों की, सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले से मिलने वाले लाभ को सम्बन्धित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच बांटा जाना समुचित होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों द्वारा तेल क्षेत्र में ‘प्रोफिट पेट्रोलियम’ में हिस्से की समान मांग पहले से ही केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।“

प्रतिस्पर्धी बोली के फलस्वरुप मिलने वाले राजस्व में राज्य के लिए हिस्सा मांगने के मामले में डॉ. रमन सिंह पूरी तरह सही हैं। कैसे इस पत्र को नीलामी का विरोध करने के रुप में उद्धृत किया जा सकता है?

अब यह सर्वत्र माना जाने लगा है कि स्पैक्ट्रम, तेल, गैस और खनिजों जैसे कीमती संसाधनों के मनमाने आवंटन की अनुमति लोगों को भ्रष्ट और कुत्सित इरादों के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराती है।

2जी स्पैक्ट्रम इसका ताजा उदाहरण था। सन् 2008 में आल इंडिया लाइसेंस का मूल्य 1658 करोड़ रुपए तय किया गया था जोकि तब बाजार मूल्य नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सन् 2012 में बाजार हालात विपरीत होते हुए भी सरकार ने 2जी का नीलामी मूल्य 14000 करोड़ रुपए स्वयं तय किया है।

यदि एनडीए की मांग कि पहले से मनमाने ढंग से आवंटित कोयला ब्लाकों को रद्द किया जाए और कोयला ब्लॉकों की नीलामी की बात स्वीकार करें तथा उसे क्रियान्वित करें तो यह सच्चाई सामने आ जाएगी कि वर्तमान में इनका उचित मूल्य वास्तव में कितना है।

♦♦♦

जब जून 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने अपुष्ट स्पष्टीकरण में संघवाद, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ही भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता ठहराया है और जिसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती, पर आरोप मढ़ा है।

के चुनाव के विरुद्ध याचिका पर फैसला सुनाते हुए लोकसभा के लिए उनका चुनाव रद्द कर दिया और आगामी 6 वर्षों के लिए उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया, तो क्रांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया।

उस महीने, वाजपेयीजी और मैं दलबदल के विरुद्ध कानून सम्बन्धी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बंगलौर गए हुए थे।

आपातकाल की उद्घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून, 1975 की देर रात्रि को हस्ताक्षर किए थे। सरकारी मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी भाई देसाई और विपक्ष के अन्य अनेक नेताओं को इसके तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून, 1975 की तड़के सुबह केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और इन सभी घटनाक्रमों की जानकारी दी गई तथा इस असाधारण कार्रवाई हेतु केबिनेट की बाद में स्वीकृति ली गई। 26 जून की सुबह वाजपेयीजी और मुझे भी बंदी बनाकर बंगलौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

बंगलौर में बंदी के दौरान मुझे आपातकाल के विरुद्ध लड़े जा रहे संघर्ष में जुटे भूमिगत पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पैम्फलेटों की श्रृंखला लिखने का अवसर मिला। इन दो पैम्फलेटों में से एक का शीर्षक था 'ए टेल आफ टू इमरजेंसीज' और 'एन एनाटॉमी ऑफ फासिज्म' जोकि नाजी जर्मनी के बारे में विलियम शिरर की प्रसिद्ध पुस्तक 'राइज ऐंड फॉल ऑफ द थर्ड राईख' पर आधारित थी। मैंने हिटलर की 1933 की इमरजेंसी और श्रीमती गांधी की 1975 की इमरजेंसी की तुलना की थी। दिलचस्प यह है कि श्रीमती गांधी आपातकाल के दौरान एक बार स्वयं लोकसभा में फासिज्म के बारे में बोलीं। 22 जुलाई 1975 को उन्होंने कहा :

"कल, विपक्ष के एक दूसरे सदस्य जानना चाहते थे कि फासिज्म क्या है। फासिज्म का अर्थ केवल दमन नहीं है। सबसे ऊपर, यह बड़े झूठ का प्रचार है, यह कानाफूसी अभियान है, बलि के बकरों की तलाश है।''

नाजी प्रचार तंत्र में 'बिग लाई' (बड़े झूठ) के सिद्धांत ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। अडोल्फ हिटलर ने इस अवधारणा को इस तरह प्रचारित किया:

"झूठ का आकार, भरोसा करने हेतु एक निश्चित कारक है लोगों के दिमागों की साधारण सहजता उन्हें छोटे, जिसे वे अक्सर स्वयं को बताते हैं कि तुलना में बड़े झूठ के लिए आसानी से वापसी हेतु प्रेरित करती है लेकिन बड़े के बताने पर उन्हें शर्म आती है।''

दिलचस्प यह है कि श्रीमती गांधी ने भारत के आपातकाल की पश्चिमी देशों की आलोचना को नाजी तरीके के 'बिग लाई' के चरित्र की भांति तब निरूपित किया कि जब उनकी बातचीत नार्थ जर्मन टी.वी. के डॉ. क्रोनजुकेर और डॉ. सचरालव से हुई। उन्होंने जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी प्रेस में प्रकाशित सामग्री पर कटुता से बोलते हुए कहा: "वे जो भी लिखते हैं वह पूरी तरह से किसी की कपोल कल्पना है। कोई यह भी नहीं कह सकता कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया है, इनमें से अधिकांश का कोई आधार ही नहीं है।''

इस तरह की आधारहीन रिपोर्टिंग के बारे में कुछ ठोस उदाहरण देने हेतु साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा आग्रह किए जाने पर प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह यह है:

"उदाहरण के लिए, एक बड़ा झूठ यह प्रचारित किया जा रहा है कि सारे आपातकाल को मेरे पुत्र सहित एक छोटा सा ग्रुप चला रहा है, एकदम निराधार है।

निर्णय इस देश के मुख्यमंत्रियों द्वारा लिया गया और ये वे हैं जो राज्यों का संचालन करते हैं।

देखिए यह एक संघीय ढांचे जैसा है अत: निर्णय मुख्यमंत्रियों द्वारा हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर लिया गया।

(पृष्ठ 166, डेमोक्रेसी एण्ड डिसिप्लेन, स्पीचेज ऑफ इंदिरा गांधी, भारत सरकार प्रकाशन)

क्या यह विचित्र नहीं है कि श्रीमती गांधी जिन्होंने आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने से पूर्व केंद्रीय मंत्रिमण्डल से परामर्श करना तक उचित नहीं समझा, परन्तु उन्हें इसके लिए मुख्यमंत्रियों को दोष देते हुए कोई संकोच नहीं हुआ?

टेलपीस (पश्च्यलेख)

सन् 1996 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त होने के बाद श्री एन. विट्ठल 1998 में मुख्य सतर्कता आयुक्त बने ओर सन् 2002 तक इस पद पर रहे।

अपनी योग्यता तथा ईमानदारी के चलते श्री विट्ठल की काफी प्रतिष्ठा रही है। उनके द्वारा लिखित नवीनतम पुस्तक "एण्डिंग करप्शन? हाऊ टु क्लीन अप इण्डिया'' (Ending Corruption How to clean up India) की प्रति मुझे हाल ही में प्राप्त हुई।

पुस्तक की प्रस्तावना में श्री विट्ठल ने लिखा कि "विशेष रूप से मीडिया में एक आम धारणा है सीवीसी जैसी संस्थाएं केवल छोटे-मोटे अपराधियों के पीछे पड़ी रहती हैं - बड़े अपराधी हमेशा बच जाते हैं।'' वे लिखते हैं:

मैंने संस्कृत के एक पुराने श्लोक को नए कलेवर में गढ़ा है जो कहता है कि भगवान भी उनकी सहायता करते

हैं जो बलवान होते हैं।

अश्वं नैव गजं नैव
व्याघ्रं नैव च
अजापुत्रं बलिं दधातु
देवो दुर्बलाघतकः

अपनी पूजा में हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं। शाकाहारी भगवान के संदर्भ में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन मांसाहारी भगवान के लिए हम कौन से पशु की बलि चढ़ा सकते हैं, अश्व की बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि केवल चक्रवर्ती (सम्राट) ही अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं यानी अश्व की बलि दे सकते हैं। हाथी की नहीं। न ही टाइगर की। तथ्य यह है कि टाइगर हमारी ही बलि ले लेगा! स्वाभाविक रूप से जो बलि चढ़ाई जाती है वह कमजोर बकरे की। यहां तक कि अंग्रेजी शब्द 'स्केपगोट' भी उसी पशु का संदर्भ है। मेरा श्लोक निम्न है:

सेक्रेटरी नैव, चेयरमैन नैव
मिनिस्टर नैव च, नैव
एलडीसी बलिं दधातु
सीवीसी दुर्बला घतकः

न तो सरकार के सेक्रेटरी या किसी संगठन के चेयरमैन की बलि चढ़ाई जाती है। मंत्री टाइगर की भांति है, कभी भी दण्डित नहीं किया जा सकता। सीवीसी केवल बेचारे लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी) को ही दण्डित करता है।

जैसाकि पहले ही वर्णन किया गया है, धारणा है कि सीवीसी सरकार के कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करता है। वास्तव में, सीवीसी का क्षेत्राधिकार ग्रुप या क्लास-1 अधिकारियों के वरिष्ठ स्तर से सम्बन्धित है, जबकि ग्रुप बी, सी और डी के सरकारी अधिकारियों का मामला उनके सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा स्वयं देखा जाता है। ■

यूपीए सरकार देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार : अरुण जेटली

संवाददाता द्वारा

गत 31 अगस्त 2012 को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कोयला घोटाले को लेकर जंतर-मंतर पर आयोजित धरने में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है, साथ ही यह सरकार नित नए घोटाले करने में मस्त है और देश की आम जनता इनके घोटालों से बुरी तरह त्रस्त है।

श्री जेटली ने बोफोर्स तोप दलाली की याद दिलाते हुए कहा कि जब देश में 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ था तो इस घोटाले के कारण कांग्रेस सरकार हार गई थी और उस घोटाले को लोग आज भी याद करते हैं। आज तो देश में इतने बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं तो देशवासी उस घोटालेबाज़ पार्टी को कैसे माफ कर सकते हैं। 2जी घोटाला कॉमनवेल्थ घोटाला, देवास घोटाला व अन्य घोटालों में प्रधानमंत्री यह कहकर बच गए कि उन घोटालों में उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस कोयला घोटाले में तो प्रधानमंत्री की सीधे जिम्मेदारी एवं जवाबदेही है, इसलिए अब वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश में कोयले की आग लगाने वाली यह सरकार सिर्फ केन्द्र सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को भी राख कर देगी। सोनिया गांधी को आड़े हाथों लेते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि इनके भ्रष्टाचारी मंत्री एवं कार्यकर्ता हमसे क्या मुकाबला करेंगे क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का नौजवान सड़कों पर उतरता है तो निर्णायक उद्देश्य की पूर्ति करके ही दम लेता है। आज अपने कुकृत्यों की वजह से कांग्रेस का अंत होने जा रहा है और अपने अंत की दस्तक भी नहीं सुन पा रही है।

श्री ठाकुर ने आगे कहा कि देश की भ्रष्ट यूपीए सरकार घोटाले पर घोटाले करती रहे और भाजयुमो का नौजवान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे, यह असंभव है।

जब तक हम केन्द्र की यूपीए सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब जरूरत आ पड़ी है कि देश का नौजवान सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को बुलन्द करे।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद सैय्यद शहनवाज हुसैन ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे घोटालों का घड़ा भरा ही नहीं बल्कि अब फूट गया है, जिसके कारण यह सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। धरने को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेन्द्र यादव, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री वाणी त्रिपाठी, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद हंसराज अहीर, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा आदि ने भी सम्बोधित किया। ■

कोयला ब्लॉक आवंटनों की संदिग्ध वकालत

✍ अरुण जेटली

Hkkरत के इतिहास में भ्रष्टाचार के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन पिछले दो दशकों से सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना हुआ है, खासतौर से जब से बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्रों का प्रवेश हुआ है। खनिज एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। खनिज आधारित उद्योगों के विकास में निजी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी इन प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की नीति विवेकाधीन रही है, जिसके कारण भ्रष्ट और गोलमाल करने की काफी गुंजाइश रह जाती है। इसलिए सरकार और शासन के कामकाज के तरीकों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि विवेकाधीन कोटे को खत्म किया जाए और निष्पक्ष मानदंड अपनाए जाएं।

अधिकतर वास्तविक संसाधन जैसे खनिज, स्पेक्ट्रम, तेल और गैस का आवंटन प्रतिस्पर्धी नीलामी के जरिये ही किया जाना चाहिए। 2जी स्पेक्ट्रम के विवेकाधीन आवंटन के परिणामस्वरुप जबरदस्त घोटाला हुआ। अब यह साबित हो चुका है कि 2008 में अखिल भारतीय लाइसेंस स्पेक्ट्रम के लिए जो 1658 करोड़ रुपये तय किये गए वह उस समय स्पेक्ट्रम की बाजार कीमत नहीं थी। प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के तहत, सरकार ने खुद 2012 में 2जी नीलामी के लिए आधार मूल्य 14,000 करोड़ रुपये तय किए। सरकारी खजाने के हितों और आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन के अधिकतम इस्तेमाल के बीच न्यायसंगत संतुलन होना चाहिए।

कोयला ब्लॉकों के आवंटन में चूक को लेकर खुसर-फुसर पिछले कुछ वर्षों से हो रही थी। सरकार ने 28 जून 2004 को सही फैसला किया था कि कोयला ब्लॉक के आवंटन की नीति में प्रतिस्पर्धा नीलामी शुरू की जाए। अगले पांच वर्षों के अधिकतर समय में प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे। 2004 और 2012 के बीच कोयला ब्लॉकों का खनन नगण्य है। इन कोयला ब्लॉकों में से अधिकतर के लिए वैधानिक और पर्यावरण संबंधी इजाजत नहीं दी गई। प्रधानमंत्री की यह दलील आंखों में धूल झोंकने वाली है कि प्रतिस्पर्धा नीलामी के लिए नीति में परिवर्तन लंबित होने के कारण, जीडीपी विकास के लिए आवंटन जरूरी था। इनमें से किसी भी कोयला ब्लॉक ने जीडीपी में योगदान नहीं दिया। उन्होंने केवल निजी क्षेत्र के आवंटियों का भारी मोल लगाया और सरकारी खजाने को चूना लगाया।

प्रधानमंत्री की बचाव की दूसरी दलील है कि प्रतिस्पर्धा नीलामी के मामले में कोयला और लिग्नाइट वाले राज्यों के विरोध के कारण उनकी सरकार बेबस हो गई थी। किसी भी संघीय व्यवस्था में, राज्यों के लिए यह जायज है कि वे अपने-अपने राज्यों में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की चिंता करें। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि एक प्रमुख खनिज के तौर पर कोयला केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उनकी सरकार ने वास्तव में 2006 में राज्यों की उपेक्षा की। वर्तमान कोयला राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने 21 दिसम्बर 2009 को संसद में स्वीकार किया कि अधिकतर राज्य प्रतिस्पर्धा नीलामी की प्रक्रिया पर सहमत हो गए हैं। इसलिए राज्यों को दोषी ठहराना बेहद खोखला बहाना है। यूपीए के भ्रष्टाचार के लिए संघीय ढांचे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रधानमंत्री का बयान संविधानवाद

इस समय प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर राष्ट्रीय बहस जारी है। इस सरकार के लिये यही बचा था कि वह अपने चहेतों को समानांतर उद्देश्यों के लिये इन संसाधनों का आवंटन करती। प्रधानमंत्री को पूरी और वास्तविक जिम्मेदारी लेनी होगी। विवेक के आधार पर किये गये इन 142 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द करें और उनकी नीलामी हो जिससे पता लगे कि उनका उचित दामों पर आबंटित किया गया।

और संवैधानिक संस्था पर हमला है। सीएजी की टिप्पणी का सम्मान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय प्रधानमंत्री ने ऐसे तर्क दिए, जो नीतिपरक शासन का अनादर है। उनकी सरकार की नीति है कि पहले संस्थाओं की अनदेखी करो लेकिन, उसके बाद भी वे न माने तो उनपर हमला करो।

प्रधानमंत्री के पास इस तथ्य का कोई जवाब नहीं है कि जून 2004 में नीतिगत फैसले के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही 11 सितम्बर 2004 को समानांतर नोट बांटा था जिसमें प्रतिस्पर्धा बोली के फैसले की कमियों को उजागर किया गया था।

कानून मंत्रालय ने ही प्रतिस्पर्धा बोली में देरी की। पहले उसने राय दी कि प्रतिस्पर्धा बोली के लिए प्रशासनिक दिशानिर्देश काफी होंगे। इसके बाद उन्होंने एक विकल्प सुझाया कि एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया जाए। दो से अधिक बहुमूल्य वर्ष बर्बाद हो गए और आखिरकार, जब एमएमडीआर (संशोधन) विधेयक को 09.09.2010 को संसद ने मंजूरी दी, यूपीए सरकार ने इसे अधिसूचित करने में 17 महीने लगा दिये। प्रतिस्पर्धा नीलामी के लिए टेंडर अभी तक तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि सरकार आवंटन में विवेकाधीन प्रक्रिया जारी रखने को लेकर अति उत्साहित थी। जब निहित स्वार्थों को अहसास हुआ कि विवेकाधीन प्रक्रिया के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तो वह स्क्रीनिंग समिति के जरिये आवंटन के लिए तैयार हो गए।

प्रधानमंत्री की आखिरी दलील कि स्क्रीनिंग समिति की व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी थी, इसका सीएजी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 4.1 में की गई टिप्पणी में दो टूक जवाब दिया है। सीएजी ने कहा है :

''यह भी देखा गया कि स्क्रीनिंग समिति ने अपनी बैठक के लिखित ब्योरे (मिनट्स) के जरिये कोयला ब्लॉक के लिए सभी आवंटियों में से एक विशेष आवंटी/आवंटियों को कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश की। हालांकि उपर्युक्त लिखित ब्योरे या कोयला ब्लॉक के लिए आवेदनकर्ता के किसी प्रकार के तुलनात्मक मूल्यांकन के बारे में अन्य दस्तावेज में कुछ दर्ज नहीं है जिस पर स्क्रीनिंग समिति भरोसा कर सके। स्क्रीनिंग समिति के मिनिट्स में इस बारे में कोई संकेत नहीं मिलता कि एक विशेष कोयला ब्लॉक के लिए प्रत्येक आवेदनकर्ता का किस प्रकार मूल्यांकन किया गया। अत: स्क्रीनिंग समिति ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए पारदर्शी तरीका नहीं अपनाया।''

आमतौर पर किसी मुद्दे पर बहस के लिए संसद एक मंच है। पीएसी ऐसा मंच है जहां सीएजी की सिफारिशों पर विचार होना चाहिए। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में सीएजी की सिफारिशों के संबंध में पिछले दिनों हमारा अनुभव यह रहा है कि सत्तारुढ़ दल ने पीएसी के जरिये उपलब्ध संसदीय जवाबदेही को खत्म करने का फैसला किया हुआ है। पीएसी को इस मुद्दे पर जानबूझकर निष्क्रिय बना दिया गया है। संसदीय गतिरोध से बचा जाना चाहिये। इस हथियार का इस्तेमाल बहुत विषम परिस्थितियों में किया जाना चाहिये। संसदीय जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी संसद में बहस। दोनों एकसाथ होने चाहिये। अगर संसदीय जवाबदेही की उपेक्षा होगी और संसदीय जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए किसी बहस का इस्तेमाल किया जाए तब विपक्ष के पास मौजूद संसदीय अधिकारों के माध्यम से सरकार का पर्दाफाश करना वैधानिक तरीका है। इस समय प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर राष्ट्रीय बहस जारी है। इस सरकार के लिये यही बचा था कि वह अपने चहेतों को समानांतर उद्देश्यों के लिये इन संसाधनों का आवंटन करती। प्रधानमंत्री को पूरी और वास्तविक जिम्मेदारी लेनी होगी। विवेक के आधार पर किये गये इन 142 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द करें और उनकी नीलामी हो जिससे पता लगे कि उनका उचित दामों पर आबंटित किया गया। ■

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

साभार : दि हिन्दू

अगर संसदीय जवाबदेही की उपेक्षा होगी और संसदीय जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए किसी बहस का इस्तेमाल किया जाए तब विपक्ष के पास मौजूद संसदीय अधिकारों के माध्यम से सरकार का पर्दाफाश करना वैधानिक तरीका है। इस समय प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर राष्ट्रीय बहस जारी है। इस सरकार के लिये यही बचा था कि वह अपने चहेतों को समानांतर उद्देश्यों के लिये इन संसाधनों का आवंटन करती। प्रधानमंत्री को पूरी और वास्तविक जिम्मेदारी लेनी होगी।

संसद में भाजपा गतिरोध पर आलोचक कांग्रेस का रिकार्ड देखें

✍ यशवंत सिन्हा

मैं अपना यह लेख ऐसे सभी आलोचकों की सेवा में रखना चाहता हूं जो निरन्तर इस बात पर बढ़चढ़ कर बोल रहे हैं कि भाजपा को संसद के कामकाज में बाधा डालना बंद करना चाहिए और लोकतंत्र को बचाना चाहिए। लोगों की याद्दाश्त बहुत कम समय तक बनी रहती है और मीडिया की याददाश्त और भी छोटी होती है। मीडिया का एक ऐसा वर्ग भी है जो कुछ बातों में किसी विशेष पक्ष के प्रति विस्मृति में डूबा रहता है।

2001 का बजट सत्र का एक बहुत बड़ा भाग तहलका स्टिंग आप्रेशन की भेंट चढ़ गया था। यही बात उस समय भी हुई जब सशस्त्र सेनाओं द्वारा खरीदे गए ताबूत की सीएजी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया था। संसद को बाधित किया गया और संसद में कांग्रेस ने जार्ज फर्नांडीस का बायकाट किया। उन्हें कफन चोर का नाम दिया गया।

वाजपेयी-नीत सरकार पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी जिसने छह वर्षो तक भारत की सत्ता संभाल रखी। उसने 1999 का चुनाव जीता और फिर सत्ता में लौटी। निश्चित ही 1998 में उसका भी हश्र पहले वाली गैर कांग्रेसी सरकारों वाला हुआ, परन्तु उसने अगले कार्यकाल में स्थिरता प्राप्त की।

उसकी सफलता से ऐसा विश्वास होने लगा था कि कांग्रेस जल्द ही फिर सत्ता में लौट नहीं पाएगी। कांग्रेस में इसके परिणामस्वरूप जो कुण्ठा पैदा हुई उसने सम्पूर्ण संसदीय आचरण को ही बदल दिया। जरा तेरहवीं लोकसभा के रिकार्ड पर मात्र निगाह डाल कर देख लें तो महसूस होगा कि प्राय: कितनी बार कांग्रेस ने संसद को बाधित किया और बाधा डालने के आधार भी कितने अधिक निरर्थक थे। मैं रिकार्ड को सामने रखने की खातिर उनका सिलसिलेवार जिक्र करना चाहता हूं और ऐसे आलोचकों की याददाश्त को ताजा करना चाहता हूं।

यदि हंगामी दृश्यों के कारण लोकसभा को बार-बार स्थगित करने की वजह से बारहवीं लोकसभा में 10.66 प्रतिशत समय बर्बाद हुआ था तो यह तेरहवीं लोकसभा में बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया।

फरवरी 2000 में, गुजरात सरकार द्वारा जारी परिपत्र में अपने कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में अनुमति देने के कारण कम से कम 10 दिनों तक लोकसभा का कामकाज ठप रखा गया था। दिसम्बर 2000 में, फिर एक बार सदन को ठप करके रख दिया था जब सीबीआई ने बाबरी मस्जिद मामले में तीन केन्द्रीय मंत्रियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

2001 का बजट सत्र का एक बहुत बड़ा भाग तहलका स्टिंग आप्रेशन की भेंट चढ़ गया था। यही बात उस समय भी हुई जब सशस्त्र सेनाओं द्वारा खरीदे गए ताबूत की सीएजी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया था। संसद को बाधित किया गया और संसद में कांग्रेस ने जार्ज फर्नांडीस का बायकाट किया। उन्हें कफन चोर का नाम दिया गया।

जब अमरीकी सेनाओं ने 2003 के आरम्भ में इराक पर हमला किया तो प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी किसी सैन्य कार्रवाई का कड़ा विरोध करने के लिए दिए गए बयान के बावजूद भी कांग्रेस ने अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने पर इसरार किया। फिर से कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही कई दिनों तक नहीं चलने दी जब तक कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हमारे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें निर्देश दिया कि कोई समझौता किया जाए और वह हमने किया भी।

इसके बाद ही तभी संसद का कामकाज चलने दिया गया। आज उस समय वाजपेयी की राजमर्मज्ञता की तुलना जरा सोनिया गांधी के लड़ने के कौशल में देखिए। हाल के वर्षो में सार्वजनिक क्षेत्र में बेलगाम भ्रष्टाचार का उदाहरण सामने है जिसे किसी और ने नहीं, बल्कि सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था ने लगाया है। देखिए, इस पर

प्रधानमंत्री ने स्थापित परम्पराओं तक का अतिक्रमण कर दिया और उन्होंने 27 अगस्त 2012 को संसद में सीएजी की आलोचना करते हुए बयान दे डाला। सचमुच यह बयान एक ऐसे व्यक्ति का बयान था जिसने अपना पूरा जीवन आर्थिक प्रशासक के रूप में बिताया और उन्हें तो सीएजी की भूमिका और जिम्मेदारी का किसी और व्यक्ति से अधिक पता होना चाहिए।

अत्यंत दुख की बात यही है कि मीडिया के एक वर्ग के सहयोग से ये लोग अपने प्रोपगेण्डा में कभी-कभी सफल हो जाते हैं, जब कांग्रेस व्यवधान डालती है तो वह अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभाती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बड़ी भारी गलती करते हैं। जब सोनिया गांधी अपने सदस्यों को लालकृष्ण आडवाणी पर हमले के लिए उकसाती है तो इसे उनका साहस और नेतृत्व का बड़ा भारी काम माना जाता है। जब प्रधानमंत्री सीएजी की आलोचना करते हैं तो उन्हें बड़ा बहादुर समझा जाता है।

हमारे आलोचक इस बारे में पूरी तरह चुप हैं। वह यह बात कहते नहीं थकते हैं कि हमारी संसदीय पद्धति में सीएजी की रिपोर्ट स्वत: ही पीएसी के पास भेजी जाती है और पीएसी इसकी जांच करता है। तो, 2जी घोटाले की रिपोर्ट पीएसी में आई। जेपीसी की हमारी मांग ठुकराने के लिए भी ठीक यही तर्क सरकार का भी है।

प्रधानमंत्री ने बार-बार अपना भरोसा पीएसी और उसके चेयरमैन पर अभिव्यक्त किया हैं। उन्होंने यहां तक कि स्वयं निजी तौर पर पीएसी के समक्ष पेश होने की बात कही है क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पीएसी मंत्रियों को नहीं बुला सकती है, यह एक ऐसी बात है जो वह जेपीसी में दोहराना ठीक नहीं समझते हैं।

सच तो यह है कि जेपीसी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को गवाहों के रूप में बुलाने के मुद्दे पर, जिसकी भाजपा मांग कर रही और सत्ताधारी पार्टी कड़ा विरोध कर रही है, गतिरोध बना हुआ है। परन्तु, हम फिर से पीएसी की ही बात करते हैं। पीएसी ने 2जी घोटाले पर चर्चा करने में आठ महीने लगा दिए।

पीएसी ने इस दौरान 22 गवाहों से पूछताछ की परन्तु जब बात कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और तत्कालीन सलिसिटर-जनरल, अटार्नी जनरल वाहनवती से पूछताछ करने की आई तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने कार्यवाही में बाधा डालना शुरू कर दिया और इन गवाहों से पूछताछ नहीं होने दी। इस पर भी हमारे आलोचक चुप हैं। बाद में, सभी संसदीय समितियों की पद्धतियों के अनुरूप पीएसी ने रिपोर्ट तैयार की।

जब इस रिपोर्ट को समिति में पेश किया तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने पीएसी की बैठक में बाधा डालने के लिए हुल्लड़बाजी शुरू कर दी। अपने लम्बे संसदीय जीवन में इससे पहले मुझे कभी ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिला। जब चेयरमैन को व्यवधान डालने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी तो सत्ताधारी पार्टी के एक सदस्य ने उनकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया और रिपोर्ट को खारिज करने की उपहासास्पद कार्यवाही का नाटक रचा। उन्होंने प्रेस सम्मेलन तक किया और चेयरमैन के लिए अश्लील शब्दों का व्यवहार किया।

यह सभी कुछ सरकार ने वरिष्ठतम मंत्रियों के निर्देशों पर किया। इस पर भी हमारे आलोचक चुप हैं। जेपीसी की प्रारूप रिपोर्ट कारगर ढंग से दफना दी गई। यही बात जेपीसी में भी दोबारा दोहराने का प्रयास हुआ। संदेश एकदम साफ और मुखर है कि ''हम तो हर तरह से भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहेंगे।''

सच्चाई यही है कि यदि कोई व्यक्ति इस सरकार के बुरे कारनामों की जांच करने की हिम्मत करता है, चाहे वह सीएजी, जेपीसी या कोई अन्य संवैधानिक संस्था हो, तो यूपीए सरकार उसे अपने संख्या बल पर कुचल कर रख देगी। सचाई को दबाया जाएगा, उनके पापों को ढक लिया जाएगा और हर बार वही बेकार का बहाना होगा कि वे तो केवल एनडीए की नीतियों का अनुसरण कर रहे थे या भाजपा भी उतनी ही दोषी है।

अत्यंत दुख की बात यही है कि मीडिया के एक वर्ग के सहयोग से ये लोग अपने प्रोपगेण्डा में कभी-कभी सफल हो जाते हैं, जब कांग्रेस व्यवधान डालती है तो वह अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभाती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बड़ी भारी गलती करते हैं। जब सोनिया गांधी अपने सदस्यों को लालकृष्ण आडवाणी पर हमले के लिए उकसाती है तो इसे उनका साहस और नेतृत्व का बड़ा भारी काम माना जाता है। जब प्रधानमंत्री सीएजी की आलोचना करते हैं तो उन्हें बड़ा बहादुर समझा जाता है। मेरी इन आलोचकों से प्रार्थना है कि वे अपनी याद ताजा करें, थोड़ा पीछे की तरफ जाएं, थोड़ी सी खोजबीन करें और फिर हमारी बात की आलोचना करें। ■

सरकार कार्रवाई न करे तो संसद में चर्चा का क्या लाभ !

✍ निर्मला सीतारमन

यूपीए शासन की बहुत सी खूबियां हैं। इनके शासन में असंख्य घोटालों की धारा बहती है, सरकार के हानि उठाने वाले निर्णयों पर सीएजी की रिपोर्ट धीरे-धीरे सामने आती है, सरकार पहले अपनी गलतियों को नकारती है, फिर उनका जवाब देने में देर लगाती है और यह सरकार सोचती है कि जवाबदेही कोई अच्छा गुण नहीं है।

सीएजी रिपोर्ट पर छाया आज के राजनैतिक संकट पर सरकार उसी रास्ते पर चल रही है जो उसने इससे पहले बड़े-बड़े भ्रष्टाचारों के आरोपों के अवसर पर अपनाया था। बात चाहे सीडब्ल्यूजी या 2जी स्पेक्ट्रम की हो या फिर इसरो-देवास और एयरसेल-मेक्सिस विवाद की हो, इसी पैटर्न को अपनाया जाता है। सरकार पहले अपनी किसी गलती को नहीं मानती है, फिर वे उस दिशा में चलने लगते हैं जिसमें वे विरोधियों द्वारा उठाए सवालों का जवाब देने में देरी करते हैं, क्योंकि वह सोचती है कि इससे समस्या अपने आप गायब हो जाएगी।

अभी उन्होंने सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था की छवि को कलुषित किया। कभी-कभी तो वे अपने ही मुख्य प्रयोजन पर सवाल खड़ा कर देते हैं। यह कांग्रेस का अजीब सा ढंग है कि वह इंस्टीट्यूशनों को प्रभावित करने की कोशिश करती है, कभी-कभी वह उनका दुरूपयोग राजनैतिक दलों को परेशान करने के लिए करती है ताकि वे यदि कोई सवाल पूछने की हिम्मत करें तो उन्हें दबा दिया और चुप करा दिया जाए और फिर सरकार भाग निकलती है। इससे भी बुरी बात यही है कि इन इंस्टीट्यूशनों का दुरूपयोग करते हुए वह छोटी/क्षेत्रीय से सदन में जबर्दस्ती उनका समर्थन मांगती है।

कुछ महीने पहले, जब सीएजी की कोयला आवंटन सम्बन्धी लीक हुई रिपोर्ट लोगों के सामने आ गई तो सरकार ने इस पर चर्चा करने से इंकार कर दिया। बाद में, मई में, जब संसद चल रही थी तो सीएजी ने सरकार को कोयले के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तब सरकार ने सत्र के आखिरी दिन भी रिपोर्ट संसद में नहीं रखी। अब जब यह प्रस्तुत हुई, इससे यह तथ्य पता चला कि जब प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था तो उस दौरान 142 कोयला ब्लाकों का जल्दबाजी में आवंटन कर दिया गया। और यह तब हुआ जब प्रतिस्पर्धा नीलामी की प्रक्रिया की नीति का निर्माण किया जा रहा था।

दरअसल, प्रतिस्पर्धा नीलामी के खिलाफ पहली आपत्ति स्वयं पीएओ ने की। बाद में, पहले विधि मंत्रालय एक परामर्श दिया और कुछ महीने बाद, इसके बिल्कुल भिन्न मत का परामर्श दिया। अभी यह सब कुछ तय ही हो रहा था, प्राइवेट आप्रेटरों का जल्दी से आवंटन कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ आप्रेटरों के पास कोयला खनन की बुनियादी क्षमता तक नहीं थी, जैसे गुटका निर्माताओं को आवंटन कर दिया। सीएजी द्वारा 1,86,000 करोड़ रुपए की दी गई राशि स्पष्ट ही प्राइवेट आप्रेटरों के लिए छप्परफाड़ बरसात की तरह पहुंच गई।

इस पूरे समय में विपक्ष के दबाव की बात छोड़िए, जब 2जी घोटाले पर चर्चा चल रही थी, सरकार तभी हरकत में आई जब न्यायालय सरकार पर हावी हो गया। यदि कोई अपराध या खजाने को नुकसान पहुंचाने की आपराधिक मंशा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होती है तो जिस नीति के कारण नुकसान हुआ, उसकी जांच संसदीय समिति से की जानी चाहिए। इस मांग को रोक कर सरकार ने अपने हठ और जिद के कारण सत्र को बर्बाद कर दिया और उसका दोष विपक्ष पर मढ़ दिया। इस प्रकार नीति अपना कर हम देखते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस उस नीति का मखौल बना रही है।

बिना सोचे समझे, सरकार ऐसे लोगों की सूची बना रही है जिन्हें जेपीसी में बुलाया जाना है। इस सूची में ऐसे लोग है जो बहुत पहले कर चुके हैं। भाजपा नेता अरुण शौरी और जसवंत सिंह ने स्वयं अपनी इच्छा से सीबीआई द्वारा पूछताछ करने को प्रस्तुत किया। इसके अलावा, सरकार वे जिद्दीपन से जुड़ते हुए, जैसे कि यह कोई सुनियोजित

ढंग हो, समझा जाता है कि कांग्रेस सदस्यों ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और जेपीसी में हंगामा किया। भाजपा के पास वॉक आऊट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह गया था।

आज भी, सीडब्ल्यूजी का मामला देश की चिंता को बढ़ा रहा है, जिसमें शुंगलु समिति की रिपोर्ट के होते हुए भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कानून का सामना नहीं करना पड़ा। शुंगलु समिति ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया। आज तक भी, सुरेश कलमाड़ी पर आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने संसद को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, परन्तु दिल्ली की कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का विरोध कर रिपोर्ट खारिज कर दी। यह है प्रधानमंत्री का वायदा।

इस पूरी अवधि में जो कदम उठाया गया वह यह था कि 'सम्बंधित मंत्री' को कानून का सामना करना था। इस मामले में, ''सम्बन्धित मंत्री'' का कदम प्रधानमंत्री की ओर इशारा करता है जो इस अवधि में कोयला मंत्रालय का काम देख रहे थे। अब, कांग्रेस पार्टी और सरकार इस कदम को उठाना नहीं चाहती है। 2जी और एयरसेल-मैक्सिस में, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम भी जांच से बच रहे हैं। तो क्या ये कदम केवल उन सम्बन्धित मंत्रियों के लिए है, जो सहयोगी पार्टियों के है, और कांग्रेस के नहीं? कैबिनेट में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के बराबर हैं।

हमें आश्चर्य होता है कि इस सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत समाप्त हो चुका है। अभी तक, प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, परन्तु इस बार वह सीधे, नैतिक और राजनैतिक रूप से जिम्मेदार हैं।

भाजपा इंस्टीट्यूशनों का सम्मान करती है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, हमारा कर्त्तव्य मात्र उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न उठाना नहीं है, बल्कि उस पर कार्रवाई की भी मांग होती है। जैसा हम देखते हैं, संसद में बहस करते समय रिकार्ड का बहुत महत्व है, अत: विपक्ष उन वायदों को भुला नहीं सकता है, जो पूरे नहीं किए गए। बहस और चर्चाएं रिकार्ड या विद्याडम्बरी मूल्यों के लिए नहीं हो सकती है जब तक उनमें सुधार न किया जाए। देखा यह गया है कि समितियों में बहस, सहयोग और संसद में चर्चा के बावजूद भी यह सरकार बार-बार कोई भी कार्रवाई करने में असफल रहती है। इस बार, हम पहले कार्रवाई करने की उम्मीद करते हैं।■

(लेखिका भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा 25 एवं 26 अगस्त, 2012 को नागपुर (महाराष्ट्र) मे दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष श्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में मुख्यरूप से श्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष, श्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन), श्री नरेन्द्र सिंह तोमर राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा एवं मोर्चा प्रभारी, श्री तापिर गांव, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, श्री महेन्द्र पाण्डेय सभी मोर्चा, एवं प्रकोष्ठ समन्वयक, श्री भगवतशरण माथुर , राष्ट्रीय संगठक मोर्चा, उपस्थित थे। बैठक का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया एवं बैठक का समापन श्री रामलाल द्वारा किया गया। बैठक में जनजाति के वरिष्ठ नेताओं में प्रमुख रूप से श्री दिलीप सिंह भूरिया, श्री नन्द कुमार साय सांसद, श्री अनन्त नायक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति मोर्चा, श्री रामसिंह राठवा सांसद, श्री नट्टूभाई पटेल सांसद, आदि उपस्थित रहें।

इस बैठक में मोर्चा के सांसदगण एवं मंत्रीगण उपस्थित रहे। मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री श्री सोम मरांडी, श्री कनकमल कटारा एवं श्री त्रिलोक कपूर उपस्थित रहे। ■

यूपीए सरकार जानती ही नहीं कि कोई संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है!

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

यूपीए सरकार का गठबंधन अन्य गठजोड़ सहयोगियों से कहीं अधिक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बीच का गठबंधन है। इसकी संचालन शक्ति श्रीमती गांधी की प्रेरणा और गतिशीलता के साथ डॉ. सिंह की खामोशी या चुप्पी में निहित रहती है। इस सरकार का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखने की बजाए कोयले की कालिख से लिखा जाएगा। इस सरकार की थोड़ी बहुत अच्छाइयां भी पहाड़ जैसी बेइंतहा घोटालों और भ्रष्टाचार की दलदल के अन्दर दफन होकर रह गई हैं। हमारे 'कमजोर' प्रधानमंत्री इस बात में मजबूती हासिल करते जा रहे हैं कि उन्होंने इस देश को इतने घोटालों की सौगात दी, जिसका कहीं कोई अंत नहीं होता है, जिसकी सबसे बड़ी राशि का उदाहरण उनके अपने कोयला और खनन मंत्रालय में 1.86 लाख करोड़ की राशि के घोटाले के रूप में देखने को मिलता है, जिसने 2जी स्पेक्ट्रम के 1.76 लाख करोड़ के घोटाले को भी मात दे दी है।

यूपीए सरकार का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखने की बजाए कोयले की कालिख से लिखा जाएगा।

भ्रष्टाचार की चमक

लगता है कि यूपीए-II भ्रष्टाचार के आरोपों से निरंतर चलते रहने के अधिक आदि हो गई है कि वह इससे छुटकारा पाना भी पाप मानती है। इसी कारण यह सरकार बड़ी बहादुरी से लोगों के सामने आकर यह कहने का साहस करती है कि ये भी हमारी महान उपलब्धियों का हिस्सा है। यह भी लगता है कि अब यह बात हमारे उन महान राजनैतिक दिग्गजों के फैशन बन गया है कि जब कभी भी वे हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसी घृणित अपराधों में पकड़े जाते हैं तो वे अपने होंठों पर बड़ी सी मुस्कान लाकर अपनी दो उंगलियों से यह संकेत करते हैं कि उन्होंने देश के कानून पर विजय प्राप्त कर ली है। और उनके समर्थक, जो प्राय: अधिकांशत: पेशेवर गुण्डे होते हैं, हंगामेदार प्रदर्शन करके अपने इन नेताओं को 'बेकसूर' घोषित करते हैं और चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं वह नेता या नेत्री साफ-पाक होकर बाहर आएंगे। वह गला फाड़-फाड़कर यह भी कहते हैं कि यह तो हमारे महान 'लोकप्रिय' नेता के प्रति 'साज़िश' है ताकि उनकी लोकप्रियता से जलने वाले विरोधी उनकी छवि धूमिल करें। महीनों तक इन कट्टर अपराधियों द्वारा जेल में एड़ियां घिसने के बाद, यदि उस नेता को अदालत से मुकदमा चलने के दौरान जमानत मिल जाती है तो उसका इतना भव्य स्वागत किया जाता है जैसे कि वह देश के शत्रुओं के (इस संदर्भ में कानून के खिलाफ) युद्ध जीत कर घर लौटा हो।

प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों की पहली प्रतिक्रिया यही रहती है कि कोई गलती नहीं की गई। 2जी घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाने तक, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ही टेलीकॉम मंत्री ए. राजा के निर्दोष होने का प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे। डॉ. मनमोहन सिंह ने बार-बार कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और जो कुछ भी राजा ने किया वह सरकार की नीति के अनुसार था। संसद में सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाने की संध्या पर प्रधानमंत्री के पास राजा से त्यागपत्र लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके त्यागपत्र के बाद जब संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह के दौरान डॉ. सिंह ने उनका स्वागत उनकी पीठ थपथपा कर किया, जिस बारे में प्रधानमंत्री ही जानते होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया।

''गलत काम या वास्तविक गलती''

राजा के त्यागपत्र के लगभग एक महीने के अंदर 17 नवम्बर 2010 को सीएजी इंस्टीट्यूशन के 150वें समारोह के अवसर पर डॉ. मनमोहन सिंह ने ऑडिट करने वाले लोगों को नसीहत दे डाली कि उन्हें 'गलत काम या वास्तविक गलती' के बीच फर्क रखना चाहिए। सरकार के ऑडिटर को अधिकारियों के निर्णय लेने के संदर्भ और हालात को समझना चाहिए और उन पर यह भारी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनकी रिपोर्ट एकदम सही, संतुलित और निष्पक्ष हो। परन्तु अभी तक प्रधानमंत्री ने यह बात साफ नहीं की है कि उनके मंत्रालय के कोयला घोटाले

के संदर्भ में 'गलत काम या वास्तविक गलती' किस श्रेणी में आती है।

जब प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर बुरी तरह दबाव पड़ा तो उन्होंने कोलगेट में लगे गम्भीर आरोपों पर मुंह खोलते हुए कम से कम अपनी बात रखने का प्रयास किया, अन्यथा उन पर न जाने कितने बिन्दुओं पर उनकी अपनी बात का खण्डन हो जाता। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को दिए 'मौनी बाबा' के रिकार्ड को तोड़ते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने बयान में शायराना ढंग से कहा: ''उन हजारों सवालों से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की जिनकी आबरू रखी ली।'' यह बात अभी देखना बाकी है कि यदि कभी उन्हें न्यायालय में उनके आचरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो क्या वह तब भी इन्हीं शब्दों को दोहराएंगे, जो उन्होंने जन-अदालत अर्थात् संसद में कहे हैं। क्या सरकार और कांग्रेस में उनके सहयोगी उनसे संकेत लेकर वही शब्द जन-अदालत अर्थात् संसद और न्यायालय में भी कहेंगे और क्या कोई भी नेता, जिस पर गलत काम या अपराध का आरोप लगा है, उस नेता के बचाव के लिए पर्याप्त होगा?

और क्या प्रधानमंत्री का यह कोरा बयान ऐसे प्रश्नों को संतुष्ट कर सकेगा, जो संसद सदस्यों के मन में 'कोलगेट' मुद्दे पर परेशान कर रहे हैं?

कोई भी डूबता आदमी स्वयं के जीवन की रक्षा के लिए तिनके का भी सहारा लेता है। और यही बात इस समय कांग्रेस पर लागू होती है। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अपनी खाल बचाने के लिए बेइंतहा बहाने बना रहे हैं।

आज कांग्रेस संवैधानिक संस्था सीएजी पर निशाना साध रही है, जो ब्रिटिश जमाने से लेकर आज तक चली आ रही है। यह वही संस्था है जिसका कांग्रेस कभी सम्मान और संरक्षण किया करती थी। जब कभी भी विपक्षी दलों द्वारा इस पर उंगली उठाई जाती थी तो कांग्रेस दूसरों को किसी संवैधानिक संस्था को निशाना न बनाने की नसीहत देती थी। परन्तु आज इसी संस्था की रिपोर्ट कांग्रेस के शब्दों में, ''ऊंटपटांग एकाउण्टिंग की कवायद'' बन गई है। परन्तु जब कभी सीएजी इसी प्रकार की रिपोर्ट गैर-कांग्रेसी राज्यों के लिए प्रस्तुत करता है तो कांग्रेस उसे ईश्वर के मुख से निकला शब्द मान कर चलती है और चाहती है कि राज्य का मंत्रिमंडल इस्तीफा दे या उसे बर्खास्त कर दिया जाए।

क्या विपक्ष का सम्मान होता है?

कांग्रेस एक और बहाना बनाती है कि बहुत से भाजपा और सीपीएम मुख्य मंत्रियों ने कोयला ब्लाकों की नीलामी का विरोध किया। अजीब सा तर्क है! भला कोई यह तो बताए कि कब से कांग्रेस ने भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया है? यह तो सचमुच 'ब्रेकिंग न्यूज' ही है कि यूपीए विपक्षी दलों और सरकारों को अत्यंत महत्व और सम्मान की दृष्टि से देखता है। अन्यथा तो भाजपा और अन्य विपक्षी राज्य सरकारों ने न जाने कितनी सिफारिशें की हैं, जो अभी तक विभिन्न मंत्रालयों में धूल चाट रही हैं। यूपीए सरकार के पास तो अभी तक पिछले कई सालों से समय तक नहीं है कि वह उन अनेकानेक विधानों पर विचार भी कर सके, जिनमें से कुछ का सम्बन्ध तो आतंकी अपराधों से है और जिन्हें विभिन्न राज्य विधानसभाओं ने पारित किया है। इन पर केन्द्र सरकार, प्रेजीडेण्ट और राज्यपाल अपनी सहमति मंजूरी रोके बैठे हैं।

अब सरकार वही बात दोहरा रही है जो उस समय दोहराई गई थी जब 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का विस्फोट हुआ था। तब यूपीए का दावा था कि वह भाजपा-नीत एनडीए सरकार की 2007 की नीति पर चल रही है। क्या इसका मतलब यह है कि वह एनडीए का अनुसरण आंख मूंद कर करती जा रही है और उसके एजेण्डा को क्रियान्वित कर रही है?

कांग्रेस ने संसद में बहुत बारीकी से रिपोर्ट पर चर्चा का बड़ी सदाकत दिखाई और यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो 'प्रधानमंत्री स्वयं स्पष्टीकरण देंगे।' उसने चुनौती दी है कि विपक्ष 'अविश्वास मत' लाकर तो दिखाए। यह सच हे कि संसद देश की समस्याओं के समाधान निकालने के लिए चर्चा करने का एक इंस्टीट्यूशन है। परन्तु, दुर्भाग्य से, संसद में हुई बहसों की निष्ठा, विश्वसनीयता और यहां तक कि शुचिता खत्म हो चुकी है। बहस का स्तर बुरी तरह गिर चुका है और बहुत हद तक संसद के भाषणों में वही बातें दुहराई जाती है जिन्हें हमारे नेता सार्वजनिक सभाओं में कहते रहते हैं।

बहस की व्यर्थता

संसद में पारित प्रस्ताव तथा बहस की शुचिता पर ध्यान न देने पर यूपीए सरकार दोषी बन कर खड़ी है। इसके मात्र एक ही दृष्टांत काफी है। पिछले वर्ष 27 अगस्त को लोकपाल बिल पर संसद के दोनों सदनों में तत्कालीन सदन के नेता श्री प्रणब मुकर्जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से 'सदन की भावना' प्रदर्शित की गई थी। क्या यूपीए ने 'सदन की भावना' का सम्मान किया? तो फिर कोयला घोटाले पर बहस या अविश्वास मत पर चर्चा करने से क्या होगा? यह मात्र एक निरर्थक कवायद होगी जिसमें बिना कोई परिणाम के

सदस्य गला फाड़-फाड़ कर बोलेंगे और जबर्दस्त गुस्सा भड़केगा।

यह बात भी ध्यान देने की है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे का समाधान निष्पक्ष जांच और कानून के द्वारा ही हो सकता है, न कि संसद में बहस करके वोट के द्वारा। संसद में बहुमत का मतलब यही है कि सरकार 'दोषी नहीं' है और वहां 'ईमानदारी तथा निर्दोष' का निर्णय नहीं हो सकता है। माफिया डॉन गवली भी महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव जीत गए थे, परन्तु यह उसके निर्दोष होने का प्रमाणपत्र नहीं है और आज उसे हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली है।

कर्नाटक में श्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ आरोपों के मामले में कांग्रेस ने यही दृष्टिकोण नहीं अपनाया। उन्हें सदन में पूर्ण विश्वासमत प्राप्त था और तब कांग्रेस ने भी अविश्वास मत पेश नहीं किया था। ये दोरंगा व्यवहार क्यों?

और याद रखिए, यह वही टेलीकॉम मंत्री हैं जिन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट का खण्डन किया था और सरकार को 'जीरो हानि' का दावा किया था। उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से भर्त्सना का सामना भी करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने 1.76 लाख करोड़ की राशि के नुकसान पर कोई सवाल नहीं उठाया।

मंत्रियों के विशिष्ट समूहों में शामिल होने वाली नवीनतम शृंखला में श्री पी. चिदम्बरम का भी नाम आता है जिन्होंने इस बात का विचित्रतम दावा किया था कि जब अधिकांश कोयला खानों में खुदाई का काम हुआ ही नहीं हो नुकसान कैसा? (हालांकि 27 अगस्त को उन्होंने अपनी इस बात से इंकार किया, जैसा कि आमतौर पर राजनेता करते हैं।) फिर यह विचित्र तर्क है। यदि खुदाई का काम नहीं हुआ तो इससे प्रधानमंत्री की कोयला ब्लाकों को गलत ढंग से आवंटन करने का आरोप खत्म नहीं हो जाता है।

इसके अलावा भी, यदि खुदाई का काम शुरू नहीं हुआ तो फिर से यह बात सिद्ध हो जाती है कि इससे देश को नुकसान पहुंचा क्योंकि इस कारण पहले तो देश में कोयले की कमी बढ़ती चली गई और दूसरे, खनन न होने से सरकार को राजस्व का घाटा हुआ, इतना ही नहीं, कि इससे देश में बिजली की कमी से स्थिति बदतर हुई।

एक तरफ, संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल संसद में चर्चा कराने के लिए बड़े उदार बनते हैं तो दूसरी तरफ वे विपक्ष की प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को बेबुनियाद और हास्यास्पद बताते हैं और यह कहते हैं कि भाजपा बिना बात का मुद्दा बना रही है। ऐसे हालात में, समझ में नहीं आता की कांग्रेस क्यों ऐसे विषय पर चर्चा करने का ढोंग रच रही है जिसे वह ''बिना बात का मुद्दा'' कह रही है, तो फिर क्यों संसद का मूल्यवान समय और पैसा बर्बाद किया जाए।

सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं?

अनेकानेक घोटालों में देश को लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। परन्तु यहां एक ऐसी सरकार है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यदि मंत्रिपरिषद जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है? अनुच्छेद 75(3) में प्रावधान है: ''मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।''

उसका सीधा सा मतलब है कि सरकार (अपने सभी भूल-चूक के कार्यों) के लिए लोकसभा में लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली होती है। 27 अगस्त को जारी अपने स्पष्टीकरण में (जिससे और कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं) अचानक ही, प्रधानमंत्री ने निर्णय लेने पर अपने ऊपर ''पूर्ण उत्तरदायित्व'' लेने की बात कही, परन्तु उसके कारण हुए 'गलत कार्यों' की जिम्मेदारी नहीं ली। जिस प्रकार से यह सरकार व्यवहार कर रही है, उससे यही लगता है जैसे उसकी सोच यह है कि घोटाले और भ्रष्टाचार के काम करना इस सरकार का अधिकार है और इससे जुड़े उनके सभी कदाचार विपक्ष और लोगों के कर्त्तव्य है।

एक बार वह समय था जब तत्कालीन रेलमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था, जिसमें 150 लोगों की जानें चली गई थीं। स्पष्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री तो खुद रेलगाड़ी नहीं चला रहे थे, परन्तु रेलमंत्री होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी.टी. कृष्णामाचारी ने भी मुंद्रा घोटाले में इस्तीफा दिया था। उन्होंने कोई घूस नहीं ली थी। परन्तु आज की कांग्रेस में चाहे जो कुछ हो जाए, कोई भी अपने को जिम्मेदार नहीं मानता है या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। केन्द्र में कांग्रेसी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। परन्तु, इस चूक के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु में एक आत्महत्याकारी बम विस्फोट में मारे गए जब वहां पर डीएमके सत्ता में थी- यह वही डीएमके है जो राज्य और केन्द्र दोनों जगह कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। जिम्मेदारी और जवाबदेह से बचना कांग्रेस और यूपीए सरकार (स्पष्ट है जिसमें उनके सहयोगी दल शामिल हैं) अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठी है। ■

(लेखक भाजपा साहित्य व प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

एकात्ममानव दर्शन के मंत्रद्रष्टा

✍ डॉ. शिवशक्ति बक्सी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे महान चिंतक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने न केवल सि)ांतों का प्रतिपादन किया वरन् अपने राजनीतिक जीवन में उन सि)ांतों पर चलते रहे। विभिन्न विषयों में दक्ष, एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की गहरी समझ एवं अपने बौ)िक क्षमताओं से भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। एक ओर जहां उनके विचार एवं दर्शन अभी भी प्रासांगिक बने हुए हैं, एक चिंतक एवं विचारक के रूप में उनके योगदान एक वैकल्पिक राजनीति एवं सुशासन के तरफ हमें प्रेरित कर राजनीति की दशा एवं दिशा के निर्धारण कार्य कर रही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते है। उन्होंने राष्ट्र को आक्रांत करने वाली समस्याओं के अलग-अलग समाधान खोजने के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया, बल्कि उनकी आकांक्षा एक ऐसे दर्शन के सृजन करने की थी जो एकात्म दृष्टिकोण के एक युग का सूत्रपात कर सके। उन्होंने शरीर, मन और बुद्धि और हर इंसान की आत्मा के एकात्मता पर बल दिया। गांधी की तरह वे भी राजनीति को अध्यात्मीकृत करने के पक्षधर थे, उन्होंने भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक लोकाचार की भाषा में राष्ट्रीय विमर्श के प्रचलन पर जोर दिया। वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्यों के लिए पश्चिम से उधार लिए गए विचारों को अपनाने के पक्ष में नहीं थे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते है। उन्होंने राष्ट्र को आक्रांत करने वाली समस्याओं के अलग-अलग समाधान खोजने के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया, बल्कि उनकी आकांक्षा एक ऐसे दर्शन के सृजन करने की थी जो एकात्म दृष्टिकोण के एक युग का सूत्रपात कर सके। उन्होंने शरीर, मन और बुद्धि और हर इंसान की आत्मा के एकात्मता पर बल दिया।

उन्होंने पूंजीवाद या साम्यवाद को मानव समाज की समस्याओं का हल कभी नहीं माना। उनके अनुसार, 'एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहली बार आर्थिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करती है, तब राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करती है, जबकि समाजवाद उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य के संपूर्ण एकाधिकार की वकालत करनी है। ये दोनों प्रणालियां मनुष्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरूद्ध हैं।'

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुख्य विचार उनकी भारतीयता, धर्म, धर्मराज्य और अंत्योदय की अवधारणाओं में देखे जा सकते हैं। भारतीयता से उनका आशय था वह भारतीय संस्कृति जो पश्चिमी विचारों के विपरीत एक एकात्म संपूर्णता में जीवन को देखती है। उनके अनुसार भारतीयता, राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि संस्कृति के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर सकती है। यदि भारत के पास दुनिया को देने के लिए कुछ है तो यह सांस्कृतिक सहिष्णुता और कर्तव्य के लिए समर्पित जीवन की भावना है। वे आगे कहते हैं, 'राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमें अपनी संस्कृति पर विचार करना होगा क्योंकि वही हमारी मूल प्रकृति है। स्वतंत्रता एक व्यक्ति की अपनी संस्कृति से लगाव से संबंधित है। यदि संस्कृति स्वतंत्रता का आधार नहीं बन पाती है, तो स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक आंदोलन स्वार्थी और सत्ता-लोलुप व्यक्तियों द्वारा छीना-झपटी में पतित हो जाएगा। स्वतंत्रता अर्थपूर्ण केवल तभी हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक उपकरण बन जाए। इस तरह की अभिव्यक्ति न केवल हमारी प्रगति के लिए योगदान करेगी बल्कि आवश्यक प्रयास हमें हर्ष का अनुभव भी देंगे'।

वे पूरी तरह से 'धर्म' की 'रिलिजन'

के रूप में व्याख्यायित करने के प्रयास के विरोधी थे। जबकि 'रिलिजन' का मुख्य रूप से पूजा की एक पद्धति के अर्थ में एक बहुत ही सीमित अर्थ है, धर्म एक व्यापक शब्द है जिसमें कई 'रिलिजन' शामिल हो सकते हैं। उनके अनुसार, 'रिलिजन' का मतलब एक पंथ, या एक वर्ग है, इस का मतलब 'धर्म' नहीं है। 'धर्म' एक बहुत व्यापक अवधारणा है। जीवन के सभी पहलुओं के साथ संबद्ध है। यह समाज को बनाए रखता है। यह पूरी दुनिया को धारण करता है। जो धारण करता है वह ''धर्म है। धर्म के मौलिक सिद्धांत अनन्त और सार्वभौमिक हैं। फिर भी समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उनका क्रियान्वयन भिन्न हो सकता है। सामान्य तौर पर नियमों और उनके दार्शनिक आधार धर्म के अर्थ से प्रेरित होते हैं।

'धर्मराज्य' का वर्णन करते समय वे राज्य को राष्ट्र के भीतर एक घटक मानते हैं, राष्ट्र के ऊपर नहीं। इस प्रकार प्रतिपादित करते हुए उनका इरादा कभी भी समाज या लोकतंत्र में राज्य के महत्व को कम करने का नहीं था बल्कि समाज और राष्ट्र के बहुलवादी चरित्र पर जोर देने का प्रयास है। एक 'जन राज्य' (लोकतांत्रिक राज्य) एक 'धर्मराज्य' भी क्यों होना चाहिए, इसका एक बहुत ही दिलचस्प स्पष्टीकरण देते हैं। वे कहते हैं, 'हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि धर्म अनिवार्य रूप से बहुमत के साथ या लोगों के साथ नहीं होता है। धर्म शाश्वत है। इसलिए, लोकतंत्र की परिभाषा में, यह कहना कि यह लोगों की सरकार है पर्याप्त नहीं है, इसे लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। धर्म अकेले निर्णय कर सकता है। इसलिए, एक लोकतांत्रिक सरकार 'जन राज्य', को धर्म, अर्थात् एक 'धर्म राज्य' में भी निहित होना चाहिए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुख्य विचार उनकी भारतीयता, धर्म, धर्मराज्य और अंत्योदय की अवधारणाओं में देखे जा सकते हैं। भारतीयता से उनका आशय था वह भारतीय संस्कृति जो पश्चिमी विचारों के विपरीत एक एकात्म संपूर्णता में जीवन को देखती है। उनके अनुसार भारतीयता, राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि संस्कृति के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर सकती है।

'लोकतंत्र' की परिभाषा, जैसे 'लोगों की लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, सरकार' में 'की' का मतलब है स्वतंत्रता, 'द्वारा' का मतलब है लोकतंत्र' और 'के लिए' इंगित करता है धर्म को। इसलिए सच्चा लोकतंत्र वह है, जहां स्वतंत्रता के साथ-साथ धर्म भी है।' धर्मराज्य की उनकी अवधारणा को निम्नलिखित गुणों से जो मौलिक सिद्धांत बनाते हैं जिन पर शासकों को कार्य करना चाहिए, अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:

(1) शासक धर्म को कायम रखने वाला है, इसका निर्माता नहीं है। न ही वह यह तय कर सकता है कि धर्म क्या है। वह केवल इसके उचित प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। धर्म का मतलब है वे शाश्वत और सार्वभौमिक नियम जो जीवन और ब्रह्मांड के लिए अनुकूल हैं - वे नियम जिनकी हमारे ऋषियों ने अपने दिव्यज्ञान के माध्यम से की खोज की थी। अन्य अर्थों में इसका मतलब राष्ट्र के जीने के तरीके की सबसे विशिष्ट और मौलिक विशेषताओं जिनके पालन पर किसी विशेष राष्ट्र की मूल दृढ़ता निर्भर करती है, में वे प्रतिबिंबित होती हैं। संक्षेप में, धर्म एक राष्ट्र की जीवन प्रक्रिया है, और यह उसे अन्य देशों अलग चिन्हित करता है। इस जीवन प्रक्रिया अर्थात् धर्म का संरक्षण करना शासक का पवित्र कर्तव्य है।

(2) जब वे एक शासक को 'राजा इति रंजति' के रूप में परिभाषित करते हैं तो धर्म राज्य में गांधीजी का रामराज्य भी समावेशित होता है। यही कारण है कि एक शासक, शासक शब्द के सही अर्थों में एक शासक होने का दावा नहीं कर सकता है जब तक वह सभी के कल्याण के लिए काम नहीं करता है। (गांधी, लोहिया और दीनदयाल, सं. पी. परमेश्वरन, डीआरआई, नई दिल्ली, 1978, पृ.40)।

अंत्योदय हालांकि गांधीवादी शब्दकोश से संबंधित एक शब्द है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में अंतर्निहित है। 'सभी के लिए शिक्षा' और 'हर हाथ को काम और हर खेत को पानी' की उनकी दृष्टि 'आर्थिक लोकतंत्र' के उनके विचार में ऊँचाई पर पहुँचती हुई दिखाई दी। आर्थिक लोकतंत्र के अपने विचार की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, 'अगर हर किसी के लिए एक वोट राजनीतिक लोकतंत्र का पारस पत्थर है तो हर किसी के लिए काम आर्थिक लोकतंत्र का एक सिद्धांत है। इस काम के अधिकार का मतलब दास श्रम नहीं है जैसा कि साम्यवादी देशों में माना जाता है। कार्य एक व्यक्ति को केवल आजीविका का साधन नहीं होना चाहिए बल्कि यह उस व्यक्ति की पसंद का होना चाहिए। अगर वह काम करते हुए श्रमिक को राष्ट्रीय आय में एक उचित हिस्सा नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगार माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से एक न्यूनतम मजदूरी, उचित वितरण प्रणाली और किसी प्रकार की एक सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों पर आधारित विकास, केंद्रीकरण, और एकाधिकार के विचारों का विरोध करते हुए उन्होंने स्वदेशी और

शेष पृष्ठ 26 पर

राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि

✍ विकाश आनंद

टर्निंग प्वाइंटस : ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस - अब्दुल ए.पी.जे. कलाम की यह पुस्तक 1992 के बाद के उनके जीवन वृत्तांत का जिक्र करता है। 'अग्नि की उड़ान' उनकी पुस्तक 1992 तक की उनकी जीवन को बताती है। एक तरह से 'टर्निंग प्वाइंटस : ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस' इस तरह की उनकी दूसरी पुस्तक है। मिसाईल मैन के रूप में जाने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम अपने जीवन का अधिकांश समय देशी प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यान तकनीकी को विकसित करने में व्यतीत किया। पोखरण-II के परीक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कलाम को परमाणविक भौतिक शास्त्र पर अधिकार नहीं होने के बावजूद भी होमी. जे. भाभा और विक्रम सारा भाई के कामों को आगे बढ़ाया।

दोनों किताबें 'अग्नि की उड़ान' और टर्निंग प्वाइंटस उस व्यक्ति के जीवन की कहानी और उसके दूरदर्शिता को व्यक्त किया है जिसने अपना जीवन एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक से शुरू कर भारत के राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। कोई 'टर्निंग प्वाइंटस' को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यह पुस्तक कलाम का जीवन कम, भारत को खुशहाल और विकसित राष्ट्र बनाना रूपरेखा अधिक है।

पुस्तक के पहले अध्याय में डॉ. अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति भवन में अंतिम दिन का जिक्र है। दूसरे अध्याय में कलाम ने बताया है कि क्यों और कैसे वे तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने लिखा है कि यह अच्छा मौका था ''भारत 2020'' के विजन को संसद और देश के सामने प्रस्तुत करने का।

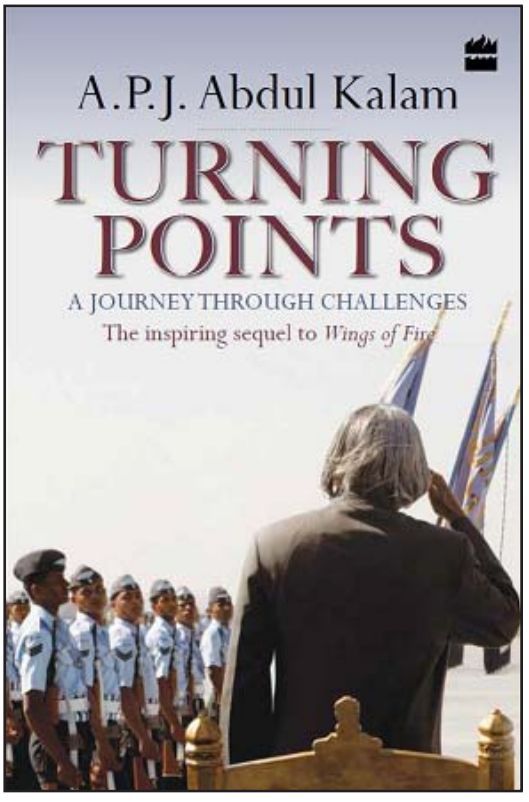

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम लिखते हैं कि मेरा अन्ना विश्वविद्यालय में नौवां व्याख्यान था। दोपहर के खाने के बाद अगली कक्षा की तैयारी के लिए अपने कमरे की तरफ लौटा तो उसी समय फोन की घंटी बजी उधर से आवाज आयी कि प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं आप से। उधर से अटल जी ने कहा कि आप 'ना' नहीं कहेंगे। वाजपेयी जी ने मुझे राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया। मैंने उनसे दो घंटे का समय सोचने के लिए मांगा फिर मैं वाजपेयी जी को 'हां' कहा। कलाम ने वाजपेयी को बताया कि मैं इसे एक महत्वपूर्ण मिशन के रूप में लूंगा।

तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है 'सेवेन टर्निंग प्वाइंटस इन माई लाईफ'। इसमें उन्होंने चौथा टर्निंग प्वाईटस 1998 के परमाणु परीक्षण को बताया है। कलाम ने इस पुस्तक में यह भी बताया है कि वाजपेयी जी मुझे कैबिनेट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन दो कारणवश मैं इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार कर सका। जिसमें एक था कि वे उस समय अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट पर थे। इसे वे पूरा करना चाहते थे। ये घटना यह भी बताती है कि अटल जी देश के विकास के लिए किस तरह से दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति का उपयोग करना चाहते थे।

चौथे अध्याय में उन्होंने बताया है कि 'भारत 2020' को आगे बढ़ाने में (promote) किस तरह से अपने कार्यकाल का उपयोग किया। उन्होंने सांसदों के साथ बैठक शुरू की। बैठक सुबह में नाश्ते के समय होती थी। प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के सांसदों के साथ अलग-अलग बैठक करते थे और उनसे क्षेत्र में विकास के

बारे में सूचनाओं और विचारों का अदान-प्रदान करते थे। उन्होंने सरकार की स्थिरता के लिए दो पार्टी वाली राजनीतिक प्रणाली का विकास जरूरी बताया।

अध्याय चार, पांच, सात और ग्यारह में न्यायिक, संसद, कार्यपालिका को अधिक कार्यपरक बनाने के कुछ सुझाव दिए हैं। वे विकास के दस स्तम्भ, न्याय में देर होने के पांच कारण, गांव के विकास का मतलब क्या होता है इस पर चार बिन्दू और सात बिन्दू संसद के कार्य पर सुझायें हैं। देश के विकास के लिए चार क्षेत्रों में ध्यान देने को कहा है वे चार क्षेत्र नैनो तकनीकी, ई-गवर्नेंस और जैव-डीजल है। छठवें अध्याय में वे अटल जी को निर्णयकारी नेता बताते हैं। वे राष्ट्र की किसी भी समस्याओं पर तुरंत निर्णय लेते थे।

इस पुस्तक में एक अध्याय राष्ट्रपति कलाम के गुजरात दौरे पर है। उसमें डॉ. कलाम बताते हैं कि लोगों द्वारा गुजरात दौरा रद्द करने के लिए कहा गया। लेकिन मैंने रद्द नहीं किया और गया।

कलाम लिखते हैं कि जब मैं गांधी नगर में उतरा तो मैं आश्चर्यचकित रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी सारी कैबिनेट और विधायक और अधिकारियों के साथ स्वागत के लिए उपस्थित थे। दंगाग्रस्त क्षेत्रों के दौरों के दौरान मोदी मेरे साथ रहे। इससे मुझे काफी मदद मिली। मैं सुझाव देता गया, मुख्यमंत्री उसे नोट करवाते गए।

कलाम साहब ग्राम विकास के अर्थ को समझाते हुए नानाजी देशमुख के दीनदयाल शोध संस्थान की तारीफ की है। नाना जी का गांव के विकास के बारे में जो सोच थी उसे मॉडल बताया है।

तेरहवें अध्याय में शिकायत के लहजे में लाभ के पद वाले विधेयक की घटना की चर्चा की है, जोकि यूपीए-I के दौरान हुआ था। उन्होंने लिखा है कि लाभ के पद वाले विधेयक को लौटाये जाने वाली घटना बताती है कि किस तरह से संसद में विधेयक पर चर्चा की गुणवत्ता के स्तर में कमी आई है।

बिल के बारे में कलाम ने कहा कि उसमें बहुत सारी असंगतियां थी। मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए कहा है कि कहा गया है कि उपहार लेने से व्यक्ति के अंदर का दैवीय प्रकाश बुझ जाता है।

इस जीवनी के प्रत्येक पन्ने से राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि झलकती है, क्योंकि उनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था और आज भी वह समर्पण जारी है। ■

पृष्ठ 24 का शेष...

विकेंद्रीकरण की वकालत की। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी प्रणाली जो रोजगार के लिए अवसर कम कर देती है अलोकतांत्रिक है। उन्होंने एक सामाजिक असमानता से मुक्त प्रणाली, जहां पूंजी और सत्ता विकेन्द्रीकृत हो जाती है की वकालत की। पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों के एक कट्टर विरोधी के रूप में उन्होंने महसूस किया है कि भारत के लिए मार्ग स्वरोजगार के क्षेत्रों से होकर निकलता है जिसमें अधिकतम उत्पादन अधिकतम हाथों को रोजगार देकर किया जा सकता है, वे एक एकात्म ग्राम के एक पक्के समर्थक थे जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो। उनका उत्पादन में वृद्धि, संयमित खपत और न्यायसंगत वितरण का एक सपना था। वे प्रकृति के शोषण के भी विरोध में थे और उन्हें लगा कि प्रकृति का हमारी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लोगों के लालच के लिए नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दुनिया के लिए संदेश हैं निम्नलिखित बिन्दुओं में देखा जा सकता है:

1. भारतीय संस्कृति की नींव पर एक मजबूत और समृद्ध भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना।
2. धर्मराज्य (जो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देता है)
3. सर्वोदय और अन्त्योदय (सभी के लिए अधिकतम कल्याण),
4. समन्वय (संश्लेषण, संघर्ष रहित जीवन के आधार के रूप में)।

आज जब हम इस महान विचारक, नेता एवं कार्यकर्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं, यह आवश्यक हो गया है कि हम उनके बताए राह पर चलें ताकि राजनीति राष्ट्र की सेवा का एक माध्यम बन सके। वैसे समय में जबकि पूरा विश्व तथा अनेक महान विचारक, दार्शनिक एवं नेता पाश्चात्य विचारों के चकाचौंध से चमत्कृत थे, तब वे भारतीय विचार एवं सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षा में डट कर खड़े रहे। वे न केवल अपनी निष्ठा पर मजबूती से डटे रहे वरन् बदलते समय के अनुरूप उन्होंने भारतीय विचार एवं मूल्यों को परिभाषित भी किया। आज हम कह सकते हैं कि वे अपने बातों पर उतने ही खरे उतरे जितना की उनकी निष्ठा एवं विश्वास सही साबित हुई है। एक ओर जहां मार्क्सवादी एवं पूंजीवादी विचारधारा ने पूरे विश्व पर कहर बरपाया है, उनके विचार जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से ओत-प्रोत हैं आज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत माता के इस महान सपूत को उनके जन्मदिवस पर हम प्रणाम करते हैं। ■

मनमोहन सरकार घोटालों के अपने ही रिकार्ड तोड़ रही है : सुषमा स्वराज

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 लाख करोड़ रूपए के कोयला घोटाले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि यदि सभी ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर फिर से कोयला खदानों की नीलामी हो जाए तो भारत के खजाने में न्यूनतम 2 लाख करोड़ रूपए आ जायेंगे। इस पैसे का उपयोग सरकार विकासकारी परियोजनाओं में करके देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकेगी।

श्रीमती स्वराज 4 सितम्बर 2012 को भाजपा दिल्ली प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक बड़ी जनसभा में बोल रही थीं। यह जनसभा मासिक बैठक के रूप में प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने बुलाई थी ताकि दिल्लीभर के कार्यकर्ताओं को इस बड़े घोटाले की बारीकियां समझ में आ सकें और वे इस घोटाले पर पूछे जाने वाले जनता के सवालों का बेबाक जवाब दे सकें। जनसभा की अध्यक्षता श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था –

हजारों सवालों से बेहतर है मेरी खामोशी,
न जाने कितने सवालों की आबरू रह गई!

जनसभा में प्रधानमंत्री की शायरी का जवाब देते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा –

तुम बोलो तो कोई बात बने,
तुम्हारी खामोशी से हजारों गलतफहमियां बनीं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि अजब बला है, मनमोहन के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचारों के अपने पुराने रिकार्ड खुद ही तोड़ रही है। पहले 70 हजार करोड़ का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ। इसके बाद 1.76 लाख करोड़ का 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाले का खेल खेला गया। अब वह रिकार्ड टूटा है और 1.86 करोड़ रूपए का कोल ब्लॉक आवंटन महाघोटाला सामने आया है। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारों की हद कर दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोटा माल कमाने के लिए ही खदानों की नीलामी करने की जो नीति 2004 में सरकार ने खुद बनाई, उसे ही कानून बनाने और उसे अधिसूचित करने में 8 साल लगाए गए ताकि इन 8 सालों में सरकार के खजाने में एक पाई न आए और कांग्रेस पार्टी के खजाने में लाखों करोड़ रूपए आ जायें। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सभी खदानों का आवंटन रद्द नहीं किया जाता और मामले की उच्चस्तरीय पारदर्शी जांच नहीं बिठा जाती, भाजपा संसद को किसी भी हाल में देशहित में चलने नहीं देगी।

अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री विजेन्द्र गुप्ता ने सभी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले को दिल्ली के हर घर हर व्यक्ति तक ले जायें ताकि लोगों को इस लूटखोर सरकार की असलियत का पता चल सके। सभा को सर्वश्री विजय गोयल, वाणी त्रिपाठी, रामेश्वर चौरसिया आदि नेताओं ने भी सम्बोधित किया। संचालन श्री आशीष सूद ने किया। आज की बैठक में तीनों नगर निगमों की मेयर श्रीमती अन्नपूर्णा मिश्रा, मीरा अग्रवाल और सविता गुप्ता भी उपस्थित थीं। इन्होंने श्रीमती स्वराज का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आज की जनसभा में महामंत्री संगठन श्री विजय शर्मा, भाजपा के विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पदाधिकारी, मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उपस्थित थे। ■

मध्यप्रदेश के युवाओं में हो रहा है राष्ट्रवाद का स्पंदन

– **रजनीश अग्रवाल**, *प्रदेश महामंत्री, भाजयुमो, मध्य प्रदेश* की रिपोर्ट

इन दिनों मध्यप्रदेश के युवा में एक नया स्पंदन है। विवेकानंद का चित्र है, जोशीले नारे है। विवेकानंद के संदेश हैं और उन्हें साकार करने वाली प्रदेश भाजपा सरकार की उपलब्धि है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 9 अगस्त से एक पूरा सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति का माहौल पूरे प्रदेश में बनाया हुआ है। क्रांति दिवस 9 अगस्त को युवा मोर्चा ने युवा क्रांति सम्मेलन का आयोजन कर पहली बार मण्डल अध्यक्षों को एक साथ एक जगह बुलाकर आगामी कार्यक्रमों का शंखनाद किया। यह स्थान मुख्यमंत्री निवास का था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेजबान भी थे और मेहमान भी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी श्री धर्मेन्द्र प्रधान इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन ने मण्डल से लेकर प्रदेश तक के आये पदाधिकारियों को न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि हौसला और जज्बा के कारण बने। श्री प्रभात झा ने राजनीति के ताने-बाने को एक नया मंत्र देकर वर्तमान दौर में मिसाल कायम की और कहा कि नये-नये युवा नेतृत्व को अगवाई करने का मौका हम देंगे और भाजपा कार्यक्रम की तैयारी करेगी। श्री प्रभात झा इस आयोजन के सूत्रधार बने और उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम तय हुए, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत महानायक स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ की तैयारी में उनके संदेश को हर युवा तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया। मध्यप्रदेश के 55 संगठनात्मक जिलों में विवेकानंद संदेश यात्राओं का आयोजन और आठ संभाग केन्द्रों पर युवा संकल्प बाइक रैली का दौर जारी है। पहले चरण में चार संभाग मुख्यालयों पर युवा संकल्प बाइक रैली का आयोजन हो चुका है, इसके पहले इन संभागों के जिलों में विवेकानंद संदेश यात्रा के माध्यम से ग्राम केन्द्र एवं नगर केन्द्र तक के युवाओं के बीच युवा मोर्चा पहुंचा। इंदौर में 19 अगस्त को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री नितिन नवीन ने युवा

आज देश का युवा भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। देश में जिस तरह से केन्द्र की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त है। ऐसे में देश की जनता की आशातीत निगाहें भारतीय जनता पार्टी की ओर है। ऐसे में हमारा सामाजिक दायित्व और भी बढ़ जाता है।

–**अरुण जेटली**, *नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा*

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पूर्ण विकास की ओर अग्रसर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जननायक बनकर उभरे है। उनकी यह उर्जा युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगी।

–**अनंत कुमार**, *राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा*

भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भविष्य उज्ज्वल है। यहां पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। यहां पर खानदान में पैदा होने वाला बेटा नेता नहीं होता है।

–**रविशंकर प्रसाद**, *राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा*

आज देश का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला कांग्रेस ने किया है और वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है। देश में महंगाई एवं भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे विकट समय में देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी प्रमुख है।

–**धर्मेन्द्र प्रधान**, *राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा*

मध्यप्रदेश में संगठनात्मक एवं रचनात्मक कार्यो के साथ आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की संरचना जो युवा मोर्चा ने तैयार की है उसे मोर्चा ने सफलता के सौपान पर पहुंचाया है।

–**नरेन्द्र सिंह तोमर**, *राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा*

प्रदेश सरकार ने युवा पंचायत बुलाकर युवाओं के सर्वांगीण विकास को केन्द्र में रखकरं प्रदेश की युवा तरूणाई को युवा-नीति देकर उन्हें आगे लाने का प्रयास किया है।

–**जे पी नड्डा**, *राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा*

युवाओं को ''कांग्रेस हटाओ-देश बचाओ'' का नारा देते हुए कांग्रेस हटाना और मध्यप्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाना है। यूपीए को हटाना है, एनडीए को लाना है। शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बने यह कार्य युवाओं को करना है।

–**अनुराग ठाकुर**, *राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजयुमो*

संकल्प बाइक रैली का प्रदेश में शुभारंभ किया। 26 अगस्त को रीवा के टीआरएस मैदान में श्री धर्मेन्द्र प्रधान एक सितम्बर को उज्जैन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं दो सितम्बर को जबलपुर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने बाइक रैलियों को संबोधित किया। हर रैली में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा पहुंच रहे है। इन रैली की तैयारियों में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन स्वयं जुटे। युवा मोर्चा की संभाग बैठकों में पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया।

युवा मोर्चा ने तय किया कि इन कार्यक्रमों का बोध वाक्य रहेगा - विवेकानंद जी का सेवा संदेश - साकार कर रहे शिवराज - मध्यप्रदेश। विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं उस प्रभु की सेवा करता हूं जिसे अज्ञानी मनुष्य कहते है। इस संदेश सहित विवेकानंद जी प्रेरणादायी मार्गदर्शन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है। विवेकानंद जी का संदेश के साथ-साथ सरकार की उपलब्धि को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवाओं के बीच ले जा रहे है। युवा संकल्प बाइक रैली के दौरान विवेकानंद युवा सम्मान अतिथियों के द्वारा युवा राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ठ कार्य करने वाले नेता को दिया जा रहा है। इंदौर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, रीवा में बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री कमलेश्वर सिंह, उज्जैन में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन और जबलपुर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते को विवेकानंद युवा सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं को एक पांच सूत्रीय संकल्प दिलाते है। जिसमें उन्हें आगे कार्य की दिशा का बोध भी कराया जाता है। इन रैलियों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कहते है कि युवा वह है जिसके पैरों में गति हो, जिसके सीने में आग हो, आंखों में शोले और अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत हो।

श्री प्रभात झा कहते हैं कि युवा मोर्चा की ये बाइक रैली नई क्रांति और परिवर्तन का वाहक बन रही है। इस आयोजन से प्रदेश के विकास को गति और कांग्रसेनीत केन्द्र सरकार की दुर्गति उजागर हो रही है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती ने स्वागत भाषण दिया।

अगले चरण में 13 सितम्बर को ग्वालियर - चम्बल संभाग की रैली को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, 16 सितम्बर को सागर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, 30 सितम्बर को शहडोल में युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित ठक्कर और समापन के आयोजन में भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी लोकसभा में नेताप्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज एवं श्री अनंत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाले है। ■

मध्यप्रदेश

रामराज्य का आदर्श प्रस्तुत करे सरकार : लालकृष्ण आडवाणी

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जब भी शासन करने का मौका मिले तो रामराज्य की तरह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। खुद ईमानदार रहें, शासन को ईमानदार बनाएं और हमेशा यह विचार करते रहें कि जनता के कल्याण के लिए क्या नए प्रयास किए जा सकते हैं। श्री आडवाणी ने कहा कि मप्र सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना और तीर्थ दर्शन योजना इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। वे 3 सितम्बर को हबीबगंज में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 1200 तीर्थयात्रियों को लेकर रामेश्वरम जाने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना में सभी धर्मो के बुजुर्गो को तीर्थयात्रा की सुविधा का उल्लेख करते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि भाजपा और रा.स्व.संघ के लोग सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार वरिष्ठजन आयोग का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस साल 31 मार्च तक 60 हजार बुजुर्गो को तीर्थयात्रा कराएगी। संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री प्रभात झा ने भी संबोधित किया। रा.स्व.संघ के पूर्व सरसंघचालक कुप्प. सी. सुदर्शन भी कार्यक्रम में पहुंचे। संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री अंबरीश कुमार मंच पर उपस्थित थे। तीर्थ दर्शन यात्रा की पहली ट्रेन करीब 1200 लोगों को लेकर रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। इसमें 984 बुजुर्ग, 16 अटेंडेंट और करीब 150 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इन तीर्थयात्रियों के साथ मुख्यमंत्री भी सपत्नीक रामेश्वरम के दर्शन करेंगे। ■

भाजपा सरकार जन-जन की हितैषी : धूमल

हाल ही इंद्र देव प्रदेश भाजपा की शिमला में हुई आभार एवं शुभकामना रैली में प्रचंड रहे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं समेत प्रदेश के नेताओ ने जोश के साथ एकजुटता का परिचय देते हुए प्रदेश में यह संदेश दे दिया कि भाजपा एकजुट होकर अपने मिशन रिपीट को सफल बनाएगी। राष्ट्र नेताओं ने जहां केन्द्र की यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर घेरा वहीं इन नेताओं ने हिमाचल में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मिशन रिपीट सफल बनाने के लिए प्रदेश की जनता से आशीर्वाद भी मांगा।

मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को भाजपा सरकार ने बिना मांगे सात हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय लाभ दिए, क्योंकि भाजपा कर्मचारियों की हितैषी है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भारी बारिश में जनता में जोश भरते हुए कहा कि हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार जैसे ईमानदार नेताओं ने हिमाचल को स्वर्ग बना दिया है। उन्होंने मुहावरे बोलते हुए कहा कि हाथी के माथे में मुक्ता मणी नहीं होती। हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर प्रदेश में धूमल जैसे नेता नहीं होते। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को घेरते हुए कहा कि उन्हें उनके सरकार होने पर भी शक है, क्योंकि अगर वो सरदार हैं, तो असरदार बिल्कुल नहीं है। उन्होंने केन्द्र की यूपीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार फैलाने में अग्रणी रही। इतिहास देश का देखा जाए, तो देश में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह हैं। आम आदमी का हाथ कांग्रेस के गाल पर

थप्पड़ मारकर गूंज रहा। आज देश में मुर्गी 75 रुपए तो दाल एक सौ दस रुपए किलो बिक रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके सरकार को प्रदेश में विकास करवाने पर बधाई दी और आगामी चुनाव में प्रदेश में मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए जनता से अपील की। उन्होंने केन्द्र की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में जो टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, उसकी अब नीलामी होने वाली है। इससे देश के खजाने में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपए आएंगे। कैग रिपोर्ट ने केन्द्र की यूपीए सरकार की हकीकत सामने ला दी है। कोयला घोटाला सामने आ गया है, लेकिन टूजी स्पेक्ट्रम में जो नीलामी होग उसका पैसा आजाद देश के खजाने में जाएगा।

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने लोगों को भाजपा सरकार को पुन: सत्ता में लाने को कहा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार अब कोयले की आग में जलकर राख होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी कोयले घोटाले में घिर चुके हैं। यूपीए के घोटालों को लेकर पूरे देश में आंदोलन किए जाएंगे। आठ साल में यूपीए ने देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ बेरोजगारी दी है।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जेपी नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में हर वर्ग का ख्याल रखा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां घर द्वार ले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में विकास किया है और अब प्रदेश सरकार पुन: सत्ता में आ रही है। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री कलराज मिश्र ने भी यूपीए सरकार को घेरा। उन्होंने धूमल सरकार द्वारा प्रदेश में करवाए गए विकास को सराहा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ध्वस्त भाजपा करेगी। देश से भ्रष्टाचार में संलिप्त यूपीए सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में खदेड़ देंगे। ■